04 - जोड़ने के लिए जाने जाएंगे चंद्रशेखर

05 - सशक्त सहभागिता और समावेशी भविष्य की आधारशिला

A Daily News Magazine
इंदौर
शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2026

06 - मुख्यमंत्री के प्रस्तावित धार भ्रमण की तैयारियाँ तेज

07 - समरसता भोज में सभी ने एक साथ बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण की

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 194, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग का हल : परमाणु ऊर्जा व थोरियम

मीनाक्षी लेखी

पिछले हफ्ते भारत के लिए एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि रही–कल्पक्कम में भारत द्वारा डिजाइन किया गया स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर 'क्रिटिकल' हुआ। इसे इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे भारत की परमाणु यात्रा में 'महत्वपूर्ण कदम' बताया। इससे देश की क्षमता बढ़ेगी कि वह जितना ईंधन इस्तेमाल करता है, उससे ज्यादा बना सके। 'क्रिटिकलिटी' वह स्थिति होती है जब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन खुद लगातार चलने लगती है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। PFBR में प्लूटोनियम आधारित मिक्स्ड ऑक्साइड ईंधन के रूप में और लिक्विड सोडियम कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। इससे भारत के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम को गति मिली है। हालांकि इसमें यूरेनियम की ज़रूरत होती है, लेकिन यह हेवी वाटर रिएक्टर के मुकाबले कम यूरेनियम में बिजली पैदा करता है।

इसका मतलब है कि भारत अपने सीमित यूरेनियम भंडार से ज्यादा ऊर्जा निकाल पाएगा। साथ ही यह थोरियम आधारित रिएक्टरों के बड़े स्तर पर इस्तेमाल का रास्ता भी खोलेगा। भारत की परमाणु यात्रा आज़ादी के बाद होमी जे. भाभा के नेतृत्व में शुरू हुई। उन्होंने एक मजबूत परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी, जिसका उद्देश्य इस शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत का शांतिपूर्ण उपयोग करना था। अपने कई पड़ोसी देशों के विपरीत, भारत ने परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल होने से इनकार किया। इसके बजाय हमने 1.5 अरब लोगों की जरूरतों को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से परमाणु ऊर्जा के जरिए पूरा करने का लक्ष्य रखा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई, ताकि तीन-स्तरीय परमाणु ऊर्जा रणनीति पर काम किया जा सके, जिससे भारत के सीमित यूरेनियम और अधिक मात्रा में मौजूद थोरियम का बेहतर उपयोग हो सके। भाभा की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए भारत का परमाणु कार्यक्रम धीमा पड़ गया, जब तक पोखरण नहीं हुआ।

पोखरण-1 ने भारत की तकनीकी क्षमता को 'शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट' के जरिए दुनिया के सामने दिखाया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण-2 हुआ, जिसने भारत को एक घोषित परमाणु शक्ति बना दिया। वैश्विक दबाव के बीच भारत ने 'विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध' और 'पहले इस्तेमाल न करने' की नीति अपनाई, जो जिम्मेदारी और संतुलन को दर्शाती है। साथ ही, भारत ने नागरिक उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा का विस्तार जारी रखा।

भारत-अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील जैसे समझौतों ने भारत को वैश्विक व्यवस्था में शामिल होने का मौका दिया, बिना परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर किए। आज भारत की परमाणु यात्रा ऊर्जा सुरक्षा, वैज्ञानिक प्रगति और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। यह आज के जटिल वैश्विक माहौल में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।

भारत के पास थोरियम के बहुत बड़े और अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल न किए गए भंडार हैं। दुनिया के कुल भंडार का लगभग 25 प्रतिशत भारत में है। ये भंडार मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और ओडिशा के समुद्री तटों की मोनाज़ाइट वाली रेत में पाए जाते हैं। ये भंडार भारत को परमाणु ऊर्जा की योजना में लंबे समय तक फायदा देने की कुंजी हैं। यह भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सकता है।

थोरियम को यूरेनियम का एक अच्छा विकल्प माना जाता है क्योंकि इससे अलग लेकिन असरदार तरीके से परमाणु ईंधन बनाया जा सकता है। हालांकि थोरियम खुद फिशाइल (टूटकर ऊर्जा देने वाला) नहीं है, लेकिन यह फर्टाइल (उपजाऊ) है। यानी यह न्यूट्रॉन को अपने अंदर लेकर यूरेनियम 233/235 में बदल सकता है, जो फिशाइल पदार्थ है और परमाणु चेन रिएक्शन को जारी रख सकता है। इसलिए यह न्यूक्लियर रिएक्टर में एक उपयोगी विकल्प बन जाता है।

थोरियम पर्यावरण के लिए भी ज्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि इससे लंबे समय तक रहने वाला रेडियोधर्मी कचरा कम बनता है और हथियार बनने का खतरा भी कम होता है। इसलिए साफ और टिकाऊ परमाणु ऊर्जा के लिए थोरियम एक अच्छा विकल्प है।

स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय शोधकर्ता आनंद जोशी की रिसर्च के अनुसार, भारत के थोरियम भंडार सैद्धांतिक रूप से मौजूदा ऊर्जा खपत के हिसाब से देश को 700 साल से ज्यादा समय तक ऊर्जा दे सकते हैं। यानी यह भारत की लंबी अवधि की ऊर्जा जरूरतों का मजबूत आधार बन सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत करता है। जैसे-जैसे हम पारंपरिक जीवनशैली से हटकर शहरी और डिजिटल सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी ऊर्जा की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल दुनिया के कारण देर रात तक काम करना बढ़ गया है। डेटा सेंटर हर साल दुनिया की कुल बिजली का लगभग 1.5 से 2 प्रतिशत (करीब 415-460 TWh) इस्तेमाल करते हैं और यह मांग हर साल करीब 12 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। अनुमान है कि AI की वजह से 2030 तक यह मांग दोगुनी हो सकती है।

खुद AI भी बहुत ज्यादा ऊर्जा लेता है। जनरेटिव AI मॉडल को ट्रेन करने और चलाने में बहुत बिजली लगती है। अनुमान है कि 2026 तक दुनिया भर के डेटा सेंटर की बिजली मांग करीब 1000 TWh तक पहुंच सकती है। इसके अलावा इन डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए भी काफी ऊर्जा चाहिए होती है। इनकी ऊर्जा जरूरत इतनी बढ़ सकती है कि कुल ऊर्जा उत्पादन का 8 प्रतिशत तक हो जाए।

इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी ऊर्जा की मांग बढ़ा रही है। ऊर्जा की मांग अब करीब 2.4 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सड़कों पर 30 प्रतिशत से ज्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक (EV) हों। लेकिन ऊर्जा की बढ़ती मांग और उत्पादन के बीच लगातार अंतर बना हुआ है। पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में मौजूदा संकट ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।

भारत के पास थोरियम के बड़े भंडार होने के कारण परमाणु ऊर्जा एक भरोसेमंद और टिकाऊ विकल्प बनती है, जो ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को कम कर सकती है। परमाणु बिजली घर मौसम पर निर्भर नहीं होते, इसलिए वे लगातार बिजली दे सकते हैं। लंबी अवधि की रणनीति यह होनी चाहिए कि देश अपने थोरियम भंडार का इस्तेमाल करके परमाणु ईंधन पर ध्यान दे। इससे आयातित ईंधन पर निर्भरता कम होगी। परमाणु ऊर्जा का विस्तार कार्बन उत्सर्जन को भी कम कर सकता है और उद्योग व शहरों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। ऊर्जा विकास के क्षेत्र में भारत अपनी क्षमता दिखाकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक उम्मीद बन सकता है, खासकर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

शरद की सुबह

रंग इस मौसम में भरना चाहिए
सोचती हूँ प्यार करना चाहिए

ज़िंदगी को ज़िंदगी के वास्ते
रोज़ जीना रोज़ मरना चाहिए

दोस्ती से तजरबा ये हो गया
दुश्मनों से प्यार करना चाहिए

प्यार का इक़रार दिल में हो मगर
कोई पूछे तो मुकरना चाहिए।

- अंजुम रहबर

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोले पीएम मोदी

नीयत में खोट को नारी शक्ति माफ नहीं करेगी

- बिल को राजनीतिक रंग न दें, जिसने भी विरोध किया, महिलाओं ने उसे माफ नहीं किया है
- इसमें राजनीतिक लाभ नहीं, मैं क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे रहा हूं
- सरकार महिला आरक्षण रोकने के लिए परिसीमन बिल लाई: कांग्रेस

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम मोदी ने गुरुवार को महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर कहा कि हमारे देश में जब जब चुनाव आया है उसमें महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिसने विरोध किया है। उसका हाल बुरे से बुरा किया है। कभी माफी नहीं मिली।

यहां कुछ लोगों को लगता है, इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। अगर साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा। फिर अलग पहलू हो जाता है। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए जैसे ही पारित हो जाए तो मैं एड देकर सबको धन्यवाद देने तैयार हूं। सबकी फोटो छपवा देंगे। ले लो जी क्रेडिट। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि इसलिए जिनको भी इसमें राजनीति की बू आ रही है वो खुद के परिणामों को देख लें। भाजपा की महिला सांसदों ने संसद के बाहर पोज दिया। भाजपा सांसद तेरश गोवाला और भाजपा सांसद जोगेन मोहन ने संसद के अंदर जाने से पहले सीढ़ियों पर झुककर प्रणाम किया।

पीएम बोले- अखिलेश मेरे मित्र, मदद कर देते हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान अखिलेश यादव को अपना दोस्त कहा। वहीं राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल से जब कहा कि आपका माइक बंद है, तो स्पीकर ने कहा– माइक सिर्फ आपका बंद होता है। उनका चालू है। इसके बाद राहुल और बिड़ला मुस्कुराने लगे। पीएम मोदी की स्पीच के दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपनी चेयर से खड़े होकर कहा– आप भी पिछड़ी जाति से हैं। पिछड़ों का ध्यान नहीं रखते। ये पूरा देश देख रहा है। इस पर मोदी ने कहा– धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी।

प्रियंका गांधी

महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि इसमें

ओबीसी का हक मिलना चाहिए। विधेयक पास हुआ तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि बिल में ओबीसी का जिक्र नहीं है।महिला आरक्षण पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सबसे पहले कांग्रेस ने ही महिला आरक्षण बिल की बात की थी। कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में खड़ी है।

गौरव गोगोई

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा– हमने कानून मंत्री की बात सुनी, उनकी बातों से लग रहा था कि पहली बार सदन के अंदर महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है। ऐसा उन्होंने ढांचा बनाने की कोशिश की। आज से ही 3 साल पहले गृह मंत्री ने ऐसी ही बातें की थीं। अगर दोनों की बातें सुनेंगे तो 90 प्रतिशत वही बातें हैं, जो आज कानून मंत्री ने कहीं। उस समय भी ऐसी ही बातें थीं।

अमेरिका ने ईरान से निकल रहे 10 जहाजों को लौटाया

- 3 दिन में एक ने भी होर्मुज क्रॉस नहीं किया; इजराइल-लेबनान की बातचीत आज

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के बंदरगाहों से निकलने की कोशिश कर रहे 10 जहाजों को वापस लौटा दिया। अमेरिकी सेना ने ईरान के समुद्री इलाके में नाकाबंदी कर रखी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, सोमवार से शुरू हुई इस नाकाबंदी के बाद अब तक कोई भी जहाज इसे पार नहीं कर पाया है।

ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई, तो वह खाड़ी इलाके में व्यापार को बाधित कर सकता है।अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि आज इजराइल और लेबनान के नेता जंग खत्म करने पर सीधे बातचीत करेंगे।

अमेरिका-ईरान शांति समझौते के करीब पहुंचे

अमेरिका और ईरान 21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीजफायर से पहले समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है, हालांकि कुछ मतभेद अब भी बाकी हैं।इस बीच तेहरान में ईरानी अधिकारियों और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच अहम बैठक होगी। मुनीर पहले ही ईरान पहुंचकर विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात कर चुके हैं और वे अमेरिकी संदेश लेकर गए हैं।

जनजातीय विकास की शक्ति का उपयोग, वंचितों-गरीबों की भक्ति के भाव के साथ किया जाए : राज्यपाल पटेल

जनजातीय समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और पेयजल की उपलब्धता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि जनजातीय विकास की शक्ति का वंचितों, गरीबों की भक्ति के भाव के साथ उपयोग करें। संवेदनशीलता और आत्मीयता के साथ किए गए कार्य ईश्वर की कृपा के भागी होते हैं। उन्होंने प्रदेश की 21 प्रतिशत आबादी के जनजातीय समुदाय के विकास के कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन की भावी रणनीति के लिए कार्यशाला आयोजन की पहल के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार ज्ञापित किया। बजट में जनजातीय विकास के लिए आवंटित राशि की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के आयोजन की मंशा है कि आगे और अधिक बेहतर किया जाए। राज्यपाल श्री पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासन अकादमी में दीप प्रज्वलित कर तथा भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनजातीय कार्य विकास मंत्री कुंवर विजय शाह उपस्थित थे।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि वर्तमान समय जनजातीय विकास का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय विकास की अभूतपूर्व योजनाएं, प्रधानमंत्री जनमन, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान आदि के अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। इनके लिए पर्याप्त बजट का भी प्रावधान किया गया है। आवश्यकता जनजातीय समुदाय के लिए अच्छा काम करने के मनोभाव और संवेदना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकासखंड, तहसील वार मूलभूत सुविधाओं का मानचित्र तैयार किया जाना चाहिए। मानचित्र में आबादी में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क आदि मूलभूत जरूरतों की उपलब्धता को अंकित किया जाना चाहिए। उसी के अनुसार जनजातीय विकास का रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि निर्धारित राशि के कार्यों के लिए वर्क आर्डर भी समय से जारी किए जाने चाहिए। जिससे राशि का समय-सीमा में उपयोग हो जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए निर्धारित राशि का समय सीमा में उपयोग बड़ी जवाबदारी है। जरूरी है कि विकास के विभिन्न कार्यों की डिजाइन, गुणवत्ता और उपयोगिता के संबंध में व्यापक चिंतन और मैदानी भ्रमण के अनुभवों के आधार पर योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी के मुख्य मंत्रित्व काल में मंत्री के रुप में कार्य के अनुभव का स्मरण करते हुए कहा कि योजनाओं का निर्माण व्यापक मैदानी भ्रमण के अनुभवों के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों, कठिनाईयों की अग्रिम जानकारी हो जाती है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए हितग्राहियों के साथ परस्पर और आत्मीय संबंधों के द्वारा समझने की जरूरत पर बल दिया। स्कूल ड्रॉप आउट की चुनौती का उल्लेख करते हुए कहा कि ड्राप आउट के कारणों को विभिन्न आयाम हो सकते है। पालकों के अशिक्षित होने से शिक्षा के महत्व का ज्ञान नहीं होना।

सुप्रीम कोर्ट ने लिए कई फैसले

पश्चिम बंगाल -एसआईआर ट्रिब्यूनल से राहत पाने वाले वोट डाल सकेंगे

नई दिल्ली(एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केवल उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलेगा, जिनके नाम ट्रिब्यूनल द्वारा क्लियर किए जा चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मामले में कहा है कि जिन मतदाताओं के नाम ट्रिब्यूनल ने 21 अप्रैल तक मंजूर कर दिए हैं, वे पहले चरण के चुनाव में वोट डाल सकेंगे। वहीं, 27 अप्रैल तक जिनके नाम क्लियर होंगे, उन्हें दूसरे चरण में मतदान का मौका मिलेगा।

चुनावों में वोटिंग अनिवार्य करने की मांग की याचिका खारिज– सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश में वोटिंग अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश नीतिगत दायरे में आता है और न्यायपालिका इसे जारी नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि जान-बूझकर वोट न डालने वालों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की मांग और वोटिंग अनिवार्य बनाने वाली याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। बेंच ने पीआईएल याचिकाकर्ता अजय गोयल से कहा कि वे अपनी शिकायतों को लेकर संबंधित पक्षों से संपर्क करें। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि जो लोग जान-बूझकर वोट डालने से दूर रहते हैं, उनके लिए सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

अशोक चक्र के लिए गाइडलाइंस की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में केंद्र और अन्य लोगों को राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र के प्रदर्शन के लिए गाइडलाइंस बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा- इन बातों को लेकर इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। आपका विचार अच्छा है। आपने जानकारी दे दी है। अब यह अधिकारियों पर है कि वे क्या करना चाहते हैं। आप समाज के लिए कुछ रचनात्मक काम करें।दरअसल, याचिकाकर्ता ने वाराणसी के एक चौराहे पर लगे अशोक चक्र की एक तस्वीर दिखाई थी।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

बंगाल में बनेगा यूपी वाला मॉडल

- सीएम योगी बोले- सड़कों पर झाड़ू लगवाएंगे

कोलकाता(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को टीएमसी सरकार पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि 15 वर्षों के शासन में उसने बंगाल को आतंक, माफिया राज, कटमनी, भ्रष्टाचार व अराजकता का अड्डा बनाकर रख दिया है। बंगाल के चुनावी रण में दूसरी बार उतरे योगी ने तीन चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के क्रम में मतदाताओं से बेखौफ होकर वोट देने की अपील करते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडे, माफिया क्या कह रहे हैं या कोई मौलाना क्या बक रहा है, आप किसी से भयभीत न होइए। डबल इंजन की भाजपा सरकार आने दीजिए, गुंडे, माफिया व मौलाना आपकी चाटुकारिता करते और बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखाई देंगे। अपराधियों व माफियाओं का इलाज केवल भाजपा की डबल इंजन की सरकार के पास है।

पश्चिम बंगाल के लोग दिल्ली के जमींदारों को मुंहतोड़ जवाब दें : ममता बेनर्जी

- प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

कोलकाता (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। यह तबादले भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए गए थे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में उठाए गए कानूनी प्रश्न को फिलहाल खुला रखा जाएगा।

भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में जानबूझकर 'अरबी संस्कृति' को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे सनातन विरासत कमजोर हो रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा पश्चिम बंगाल को 'बंगाली हिंदुओं की मातृभूमि' के रूप में सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाताओं से कहा कि वे दिल्ली के जमींदारों द्वारा लोगों के मतदान के अधिकार छीनने के प्रयासों का मुंहतोड़ जवाब दें।

नोएडा बवाल में एक और खुलासा

- पाकिस्तानी एक्स हैंडलर की साजिश, सीमा पार से भड़काए गए थे श्रमिक

नोएडा (एजेंसी)। शहर में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन और आगजनी के पीछे पाकिस्तान से संचालित एक्स हैंडलर का हाथ सामने आया है। पुलिस ने दो ऐसे एक्स हैंडलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में अब तक 13 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने यह जानकारी दी। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर भड़की इस हिंसा की चिंगारी तेलंगाना और कर्नाटक से वॉट्सऐप के जरिये आई थी। कुछ लोगों की डिजिटल ट्रेल मिली है। सोमवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद बुधवार रात तक करीब 600 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकतर गिरफ्तारियां कोतवाली फेज वन, फेज टू, सेक्टर-58, सेक्टर-63 और फेज थ्री से हुई हैं।

कटे हुए हाथों से लड़ी थी 10 डकैतों से जंग

- अब 44 साल बाद राजस्थान पुलिस ने शहीद मानसिंह को दिया 'अमर' सम्मान

बांसवाड़ा (एजेंसी)। राजस्थान पुलिस के इतिहास में वीरता की कई कहानियां दर्ज हैं, लेकिन कुछ पन्ने समय की धूल में दब जाते हैं। 44 साल पहले बांसवाड़ा की धरती पर एक सिपाही ने बैंक बचाने के लिए अपने दोनों हाथ कटवा दिए थे, लेकिन फर्ज से पीछे नहीं हटा। गुरुवार को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर जब बांसवाड़ा पुलिस लाइन में शहीद कॉन्स्टेबल मानसिंह की बहादुरी का किस्सा फिर से गूंजा, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं और सीना गर्व से चौड़ा हो गया।

वह खौफनाक रात: जब एक सिपाही 10 डकैतों पर भारी पड़ा- घटना 3 मार्च 1982 की है। सन्नाटे को चीरते हुए सूचना मिली कि घाटोल स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में 8-10 हथियारबंद डकैत घुस आए हैं। ड्यूटी पर तैनात कॉन्स्टेबल मानसिंह के पास विकल्प था कि वे बैकअप का इंतजार करें, लेकिन उन्होंने 'फर्ज' को चुना। मानसिंह अकेले ही डकैतों के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने एक लुटेरे को दबोच लिया, तो बाकी डकैतों ने उन पर तलवारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

दोनों हाथ कटकर शरीर से अलग हुए- वार इतने घातक थे कि मानसिंह के दोनों हाथ कटकर शरीर से अलग हो गए। लहूलुहान और निहत्थे होने के बावजूद मानसिंह ने डकैतों को बैंक लूटने नहीं दिया।

एसपी की एक पहल ने लौटाया 'शहीद' का सम्मान

दशकों तक यह फाइल रिकॉर्ड रूम में दबी रही। लेकिन बांसवाड़ा एसपी सुधीर जोशी ने जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले, तो मानसिंह के इस सर्वोच्च बलिदान की कहानी उनके सामने आई। एसपी को लगा कि जिस जवान ने फर्ज के लिए अपने अंग कटवा दिए, उसे वह सम्मान अब तक नहीं मिला जिसका वह हकदार था। उनके सम्मान में पुलिस लाइन के चिल्ड्रेन्स पार्क का नाम अब 'शहीद मानसिंह बालोद्यान' रखा गया है। पुलिस लाइन में मानसिंह की तस्वीर लगाई गई है ताकि नए जवान उनके साहस से प्रेरणा ले सकें।

आज दोनों बेटे निभा रहे हैं 'खाकी' का फर्ज

अनाथ होने के बाद मामा के संरक्षण में पले मानसिंह के दोनों बेटे आज भी सिस्टम का हिस्सा हैं। छोटे बेटे करण सिंह पुलिस में चौकी प्रभारी हैं, वहीं बड़े भाई दिगपाल सिंह अभियोजन विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। करण सिंह कहते हैं, आज 44 साल बाद जब विभाग ने पिता को याद किया, तो लगा कि उनकी शहादत अमर हो गई। बांसवाड़ा पुलिस की यह पहल उन तमाम गुमनाम शहीदों के लिए एक उम्मीद है, जिन्होंने खाकी की आन-बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

शहादत के बाद उजड़ गया पूरा परिवार

शहीद मानसिंह के बेटे और वर्तमान में जगपुरा चौकी प्रभारी करण सिंह बताते हैं कि वह रात सिर्फ उनके पिता को नहीं ले गई, बल्कि पूरे परिवार को लील गई। मानसिंह की शहादत के गम में महज दो महीने बाद छोटी बहन की मौत हो गई। पिता के कटे हुए हाथ और वियोग का सदमा मां नारायण कुंवर बर्दाश्त नहीं कर पाईं और जून 1982 में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। 5 और 7 साल के दो मासूम बच्चे (करण और दिगपाल) पूरी तरह अनाथ हो गए।

सीएम डॉ.यादव बोले

कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब होते दिख रहा

महिला बिल का विरोध करेंगे तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा ये कांग्रेस सोचे

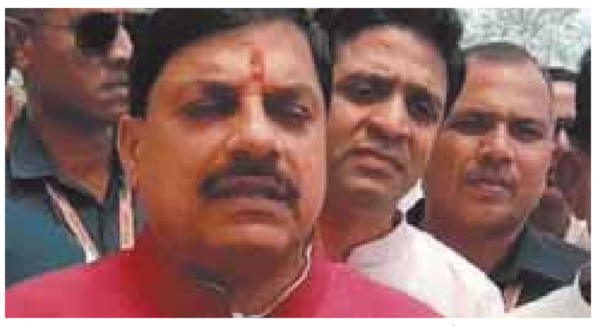

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा क्रांतिकारी निर्णय बताया, जिसने सदियों के इंतजार को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कड़े और सीधे शब्दों में कहा यदि कांग्रेस विरोध करेगी तो जनता में गलत संदेश जाएगा।

1971 की बेड़ियों से मुक्त होगा लोकतंत्र- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का यह निर्णय साधारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को सींचने वाला है। हम अब तक 1971 की जनगणना के आधार पर चल रहे परिसीमन को ढो रहे थे, लेकिन अब नया परिसीमन हमारे लोकतंत्र को नई ऊर्जा और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। यह अधिनियम हमारी बहनों के लिए वह द्वार खोलेगा, जहां से आधी आबादी को शासन और नीति-निर्धारण में अपना पूरा बल और अधिकार मिलेगा।

कांग्रेस की नीति और नियत में खोट- विपक्ष की दोहरी राजनीति पर गरजते हुए डॉ. यादव ने कहा, कांग्रेस की नीति और नियत में हमेशा से फर्क रहा है। वे कहते तो हैं कि हम महिला आरक्षण चाहते हैं, लेकिन उनकी नीयत में खोट साफ दिखाई देती है। आज वे बेनकाब हो चुके हैं। जिस बिल को सर्वसम्मति से पारित कर एक उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए था, उस पर कांग्रेस मीन-मेख निकाल रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई बात है तो सदन के फ्लोर पर कहें, जनता के बीच जाकर इस क्रांतिकारी कदम का विरोध करना आपकी महिला विरोधी मानसिकता का प्रमाण है।

तीन तलाक का पाप धोने के बजाय, नए पाप की तैयारी में विपक्ष- मुख्यमंत्री ने इतिहास के घावों को कुरेदते हुए तीखा हमला बोला: कांग्रेस यह न भूले कि तीन तलाक जैसी अमानवीय प्रथा को ढोने और उसे संरक्षण देने का पाप उन्हीं के माथे पर है। आज जब हमारी सरकार बहनों को सशक्त कर रही है, तब भी कांग्रेस को पीड़ा हो रही है। आधी आबादी सब देख रही है और वह सोच रही है कि आखिर कांग्रेस उनका अहित क्यों चाहती है? यही कारण है कि जनता का भरोसा खोने की वजह से कांग्रेस का जनाधार लगातार गिरता जा रहा है।

हम जो करते हैं, खुले मन से कहते हैं- सशक्तिकरण हमारी प्रतिबद्धता

अपनी सरकार और पार्टी का पक्ष रखते हुए डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया, भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी की महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्धता चट्टान की तरह अडिग है। हम राजनीति के लिए काम नहीं करते, हम समाज सुधार के लिए निर्णय लेते हैं। जो हम करते हैं, वह खुले मन से और पूरी स्पष्टता के साथ कहते हैं। यह अधिनियम महिलाओं के सम्मान और भागीदारी का वह नया अध्याय है, जिसे अब कोई भी नकारात्मक राजनीति नहीं रोक पाएगी।

पॉलिटेक्निक कालेज के विद्यार्थियों को मिलेगी सौ सीटर छात्रावास की सुविधा : उप मुख्यमंत्री

रीवा बायपास के पुल का सुधार कार्य 15 दिन में पूरा कराएं

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने नवीन सर्किट हाउस सभागार रीवा में आयोजित बैठक में विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलिटेक्निक कालेज के विद्यार्थियों के लिए सौ सीटर छात्रावास निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। छात्राओं के लिए कालेज परिसर तथा छात्रों के लिए राजस्व अधिकारी द्वारा निराला नगर में चिन्हित जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कराएं। इसके साथ-साथ पॉलिटेक्निक कालेज को 144 लाख रुपए की लागत से स्पोर्ट्स काम्पलेक्स निर्माण की भी मंजूरी दी गई है। तकनीकी अधिकारी स्वीकृत कार्यों को तत्काल शुरू कराएं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बायपास मार्ग में पुल के सुधार का कार्य 15 दिन में अनिवार्य रूप से पूरा कराएं। पुल से आवागमन बंद होने के कारण रीवा शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में जाम लगने के कारण आमजनता को कठिनाई हो रही है। रात में भी विवाह समारोहों के कारण सड़कों पर चहल-पहल रहती है। ऐसे में भारी वाहनों को शहर से निकालना भी कठिन है। बायपास रोड के चौड़ीकरण का कार्य भी तय समय सीमा में पूरा कराएं। कलेक्टर निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सोहागी घाट में दुर्घटनाएं रोकने के लिए सुधार कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो गई है। इसके लिए 14 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर कर दी गई है। वन मण्डलाधिकारी निर्माण कार्यों के लिए शीघ्र स्वीकृति जारी कराएं जिससे निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सोहागी घाटी में सुधार आवश्यक है। बैठक में एमपीआरडीसी के प्रभारी जीएम अंशुल करोड़िया ने बताया की बायपास में पुल के सुधार का कार्य 30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। सोहागी घाटी में निर्माण कार्य के लिए वन विभाग द्वारा पूर्व में अनुमति दी गई थी। नवीन कार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है। अनुमति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल, अध्यक्ष नगर निगम श्री व्यंकटेश पाण्डेय, प्रभारी आयुक्त नगर निगम मेहताब सिंह गुर्जर, वन मण्डलाधिकारी लोकेश निरापुरे, श्री शैलेन्द्र शुक्ला, एसडीएम हुजूर डॉ. अनुराग तिवारी तथा निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मप्र पुलिस में आरक्षक (बैंड) के 679 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा पुलिस बैंड के अंतर्गत आरक्षक (बैंड) के कुल 679 पदों पर सीधी भर्ती वर्ष 2026 हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती प्रक्रिया विशेष रूप से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2026 निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। इच्छुक एवं पात्र पुरुष अभ्यर्थी अब दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक एमपी ऑनलाइन की वेबसाईट ttps:// iforms. mpon-line.gov.in पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला

स्पाइसजेट और अकासा एयर के विमानों के पंख आपस में टकराए; सभी यात्री सुरक्षित

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार को स्पाइसजेट के एक बी 737-700 विमान के साथ ग्राउंड पर हादसा हुआ। टैक्सी करते समय यह अकासा एयर की प्लाइट से टकरा गया। स्पाइसजेट के प्रवक्ता के मुताबिक, इस घटना में स्पाइसजेट विमान का राइट विंग क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं, दूसरे विमान के लेफ्ट हैंड हॉरिजॉन्टल स्टैबलाइजर को भी नुकसान पहुंचा है घटना के बाद स्पाइसजेट का यह विमान दिल्ली में ही ग्राउंड कर दिया गया है। फिलहाल इसे उड़ान के लिए उपयोग में नहीं लिया जा रहा है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित 16 सदस्यों ने राज्यसभा सांसद पद की शपथ ली

नईदिल्ली (एजेंसी)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री राम नाथ ठाकुर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने, 13 अन्य नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों के साथ, गुरुवार को सांसद पद की शपथ ली। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने बिहार, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा के 16 नवनिर्वाचित/पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई।

लखनऊ अग्निकांड से कई गृहस्थी उजड़ी

- 2 बहनें जिंदा जलीं, 250 परिवार बेघर
- राख में मिलीं फ्रिज, बाइक

लखनऊ (एजेंसी)। लखनऊ में बुधवार को लगी आग में 250 से ज्यादा झोपड़ियां राख हो गईं। 2 मासूम बहनें जिंदा जल गईं। इनमें एक 2 साल तो दूसरी 2 महीने की थी। गुरुवार सुबह घटनास्थल पर सिर्फ राख और जल चुका गृहस्थी का सामान नजर आया। बेघर हुए ये लोग राख में सामान तलाश रहे हैं। अलमारी, फ्रिज, बाइक जैसी चीजें राख में मिल गईं। बेघर हुए कुछ परिवारों को अफसरों ने रात में ही रैन बसेरों में भेजा था, जबकि कुछ ने पास के खाली प्लॉट में रात बिताई। महिलाओं ने रोते हुए आरोप लगाया कि कोठीवालों ने उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी। उन्हें पहले धमकाया गया था कि झोपड़ियां हटा लो, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। हम नहीं हटे, तो झोपड़ियों में आग लगा दी। उन्होंने यह भी कहा कि जिंदगी भर की कमाई राख हो गई। अगर समय पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच जाती, तो कुछ सामान बच सकता था।

लॉरी और कार की टक्कर, कर्नाटक के 8 तीर्थयात्रियों की मौत

नईदिल्ली (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के चिलकलाडोना के पास एक लॉरी और कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई है। 10-12 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए एम्मिगनूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुरनूल पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतकों की पहचान कर्नाटक (चिक्कमगलुरु क्षेत्र) के तीर्थयात्रियों के रूप में हुई है।

चीन से जंग के मूड में जापान

- 81 साल बाद युद्धाभ्यास के लिए भेज रहा सेना, जल, नभ और आकाश में ट्रेनिंग

टोक्यो/मनीला (एजेंसी)। चीन दुनिया की सबसे बड़ी सेना बनाकर अपने पड़ोसी देशों को डराने में जुटा हुआ है। चीन की कोशिश है कि ताइवान सबसे पहले उसके आगे सरेंडर करे। ताइवान के पड़ोसी जापान और फिलीपींस ताइपे को 'फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस' मानते हैं। इसी वजह से अब जापान और फिलीपींस दोनों ने अपनी सैन्य तैयारी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि जापान दूसरे विश्वयुद्ध की छाया से निकलते हुए 81 साल बाद फिलीपींस में सैन्य अभ्यास के लिए अपनी सेना को भेज रहा है। इस साल अमेरिका, फिलीपींस और जापान मिलकर बड़े पैमाने पर बालिकतान युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। इसके लिए जापान एक बहुत बड़ी और मल्टी सर्विस सेना को भेज रहा है।

अब तक जापान मानवीय मदद और आपदा राहत के नाम पर सेना की छोटी सी टुकड़ी को भेजता रहा है लेकिन इस बार उसने फिलीपींस में हो रहे युद्धाभ्यास में विशाल सेना को भेज रहा है। इस बार जापानी सैनिक जंग की ट्रेनिंग लेंगे। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जापान की सेना 1400 ऐसे सैनिकों को भेज रही है जो जमीन और पानी दोनों में लड़ने में माहिर हैं। इसके साथ एक डेस्ट्रायर समेत 3 युद्धपोत भी भेजे जा रहे हैं। यही नहीं जापान की जमीनी सेना भी अपने हथियारों के साथ फिलीपींस जा रही है।

यूपी के संभल में ईदगाह-इमामबाड़े को बुलडोजर से ढहाया

भीड़ जुटी तो अफसरों ने खदेड़ा

संभल (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के संभल में ईदगाह और इमामबाड़े पर गुरुवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक बुलडोजर की कार्रवाई चली। इसमें ईदगाह और इमामबाड़ा गिरा दिया गया। इमामबाड़े को तोड़ने के लिए चार बुलडोजर लगे। मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स और एक कंपनी पीएसी तैनात रही। इसी बीच, गांव के लोग मौके पर जुट गए। विरोध की आशंका को देखते हुए अफसरों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। प्रशासन के मुताबिक, करीब 7 बीघा चारागाह की जमीन पर ईदगाह और खाद गड्ढे की भूमि पर इमामबाड़ा बनाया गया था।

इंदौर में सिटी बस पास 400 रुपए महंगा, छात्र भड़के

नगर निगम मुख्यालय में प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा; भोपाल कूच करने की चेतावनी

इंदौर (नप्र)। इंदौर में सिटी बस पास का दाम 400 रुपए बढ़ने से छात्र नाराज है। इसके विराध में छात्र नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। सिटी बस पास का दाम करने के लिए उन्होंने ज्ञापन भी दिया। छात्रों के हाथों में तख्तियां थी, जिस पर लिखा था छात्रों को एटीएम मशीन समझना बंद करो, छात्रों के साथ अन्याय के खिलाफ एकजुट हो। प्रदर्शन करने वालों का कहना था कि जो छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहां आए हैं, वे एक टाइम भूखा रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्रशासन ने एक बार भी नहीं सोचा कि सिटी बस के पास का दाम बढ़ाने से इन छात्रों का क्या होगा। मूसाखेड़ी से जीडीसी कॉलेज छात्राएं जाती है, दोनों तरफ का किराए 50 रुपए रोज का लगता है, क्या ये छात्राएं इतना किराया रोज का दे सकती है। नगर निगम इतना टैक्स ले रहा है, उसमें क्या छात्रों का बस पास माफ नहीं किया जा सकता है। जयस छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष पवन अहिरवार ने बताया कि महापौर बस पास योजना को खत्म कर दिया है। स्टूडेंटस पास जो 200 रुपए का था, उसे 600 रुपए कर दिया गया है। निगम अधिकारियों के लिए महापौर के लिए ये 600 रुपए आम राशि होगी, लेकिन इंदौर में जो गरीब व मध्यमवर्ग का छात्र यहां रहकर पढ़ाई कर रहा है। 600 रुपए किसी छात्र के माता-पिता की तीन दिन की दिहाड़ी-मजदूरी हो सकती है। इसलिए जो पास में वृद्धि की है, उसे कम करने की मांग लेकर नगर निगम आए।

चौराहे की समस्या बताई, सफाई की मांग की

इसके साथ ही उन्होंने भंवरकुआं स्थित टंट्या भील चौराहे पर गंदगी फैली हुई है। यहां पानी, सफाई की व्यवस्था है। नगर निगम से मांग की है कि यहां साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए। तमाम छात्र संगठन द्वारा ज्ञापन दिया है, अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो 15 दिन बाद सभी छात्र संगठन द्वारा नगर निगम का घेराव करेंगे। फिर भी मांग नहीं मानी तो भोपाल कूच करेंगे।

निगम कमिश्नर-महापौर तक पहुंचाएंगे छात्रों का ज्ञापन- वीरेंद्र उपाध्याय, प्रभारी कंट्रोल रूम ने बताया कि छात्रों का कहना था कि सिटी बसों के जो पास बनते है उसमें 400 रुपए की वृद्धि की गई है। इस संबंध में छात्रों ने ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल और महापौर पुष्यमित्र भार्गव तक पहुंचा दिया जाएगा। वहीं चौराहे को लेकर जो शिकायत की है, उसका निराकरण करा दिया जाएगा।

प्रचंड गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने लिया फैसला

इंदौर में बदला नर्सरी से आठवीं तक के स्कूलों का समय

इंदौर (नप्र)। मध्य प्रदेश में अब भीषण गर्मी पड़ने लगी है। इस देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब जिले के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

आंगनवाड़ी केंद्रों का भी बदला समय- सिर्फ स्कूल ही नहीं आंगनवाड़ी केंद्रों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। अब आंगनवाड़ी सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगी, जबकि कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की अन्य गतिविधियां पूर्व निर्धारित समय अनुसार जारी रहेंगी।

बुधवार को 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था तापमान- दरअसल, बुधवार को इंदौर में तापमान 41

डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान माना जा रहा है। तेज धूप और लू जैसे हालात को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है ताकि छोटे बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके।

गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की- वहीं, मौसम विभाग ने भी प्रदेश में गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के अनुसार मध्यप्रदेश के 16 जिलों में लू चलने की संभावना है। इनमें रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट शामिल हैं।

महापौर सचिवालय में हुआ नारी संवाद

महापौर बोले- हर सेक्टर में 30 प्रतिशत तक महिलाएं कर रहीं नेतृत्व, आतिशबाजी की

इंदौर (नप्र)। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में गुरुवार को महापौर सचिवालय में नारी संवाद हुआ। कार्यक्रम महापौर पुष्यमित्र भार्गव और भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया। महिलाओं ने इसमें भाग लेकर अपने विचार साझा किए और इस विधेयक को अपना समर्थन दिया। महापौर ने कहा कि पिछले 15-20 सालों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है और लगभग हर सेक्टर में 30 प्रतिशत तक महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। ऐसे में यह अधिनियम इस बदलाव को और गति देगा व महिलाओं के निर्णय लेने की मुख्यधारा में लाएगा। महापौर और भाजपा नगर अध्यक्ष ने महिलाओं से संवाद करते हुए अधिनियम के महत्व और संभावित प्रभावों के बारे में विस्तार से बातचीत की। महापौर बोले यह कानून केवल महिलाओं के सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं द्वारा सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह आने वाली पीढ़ियों की दिशा और दशा तय करने वाला परिवर्तनकारी कानून साबित होगा। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने भी अधिनियम की आवश्यकता और उसके दूरगामी प्रभावों पर रोशनी डाली। वे बोले यह बिल महिलाओं की नीति-निर्माण में ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करेगा। यहां मौजूद महिलाओं ने भी अपने विचार रखते हुए विधेयक का समर्थन किया। महिलाओं ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब केवल उनके लिए नीतियां नहीं बनेंगी, बल्कि महिलाएं स्वयं नीतियां बनाएंगी और देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। महिलाओं ने मेयर व भाजपा नगर अध्यक्ष के साथ आतिषबाजी की और मिठाई बांटी। महापौर बोले 18 अप्रैल को, जिस दिन यह बिल पारित होगा, उस दिन इंदौर की महिला शक्ति सड़कों पर उतरकर इस ऐतिहासिक क्षण का उत्सव मनाएगी।

'वंदे मातरम्' की गरिमा पर हाईकोर्ट सख्त

इंदौर बेंच ने पार्षद रुबीना खान और फौजिया शेख को जारी किया कारण बताओ नोटिस

इंदौर (नप्र)। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के समक्ष राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के गायन के दौरान सरकारी और सार्वजनिक मंचों पर गरिमापूर्ण आचरण सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचा बनाने की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका दायर की गई है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए मामले से जुड़े पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह कार्रवाई इंदौर नगर निगम की एक हालिया घटना के बाद शुरू हुई, जिसमें राष्ट्रीय गीत के दौरान हुए विवाद ने प्रदेशभर का ध्यान आकर्षित किया था।

प्रभावी नियामक ढांचे की मांग

याचिकाकर्ता और एडवोकेट योगेश हेमनानी ने स्वयं न्यायालय के समक्ष पक्ष रखते हुए दलील दी कि वर्तमान में शासकीय संस्थानों में 'वंदे मातरम्' के उच्चारण के समय आचरण और अनुशासन को लेकर कोई प्रभावी नियामक ढांचा मौजूद नहीं है। उन्होंने कोर्ट से प्रार्थना की कि राष्ट्रीय गीत की गरिमा बनाए रखने के लिए स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

याचिका में संविधान के अनुच्छेद 51ए का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के आदर्शों और प्रतीकों का सम्मान करे। ऐसे में सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का आचरण मर्यादित और आदर्श होना चाहिए।

शासन से भी मांगा जवाब

मामले की गंभीरता को देखते हुए बेंच ने प्रमुख सचिव, गृह सचिव सहित अन्य संबंधित शासकीय विभागों को भी सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा है। यह प्रकरण वर्तमान में कोर्ट के विचाराधीन है। याचिका के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि भविष्य में किसी भी सार्वजनिक अथवा सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत के गायन के समय अनुशासन और सम्मान की भावना अक्षुण्ण बनी रहे।

खजराना के पुजारी पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज

दूसरी पत्नी महिला थाने पहुंची, 1 करोड़-फॉर्च्यूनर के लिए प्रताड़ना के आरोप

इंदौर (नप्र)। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर से जुड़े पुजारी पुनीत भट्ट के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। महिला का कहना है कि आरोपी पति और ससुराल पक्ष द्वारा 1 करोड़ रुपए नकद और फॉर्च्यूनर कार की मांग की जा रही थी। महिला थाना टीआई श्रद्धा यादव ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद मामले की जांच की गई। सभी पक्षों के बयान लिये गए। इसके बाद केस दर्ज किया है। पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पहले जनसुनवाई में आवेदन लेकर दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। जांच के बाद पुजारी पुनीत भट्ट के खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

22 दिन पहले भी की थी शिकायत- इससे पहले करीब 22 दिन पहले पीड़िता इंदिरा भट्ट ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में जनसुनवाई में भी शिकायत दी थी। इसमें पति पुनीत भट्ट सहित सास, ननद, नंदोई और देवरों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। महिला ने दहेज प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और घर से निकालने की बात कही थी।

शादी के बाद बदला व्यवहार

पीड़िता के अनुसार उसकी शादी 17 मई 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। यह दोनों की दूसरी शादी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जुलाई 2025 के बाद ससुराल पक्ष का व्यवहार बदल गया। इसके बाद लगातार दहेज के लिए दबाव बनाया जाने लगा।

1 करोड़ और फॉर्च्यूनर की मांग का आरोप

महिला का आरोप है कि पति और ससुराल पक्ष ने मायके से 1 करोड़ रुपए और फॉर्च्यूनर कार लाने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और अपमानित किया गया।

इंदौर में हेलमेटधारी बदमाश ने दो दुकानों में की चोरी

इंदौर (नप्र)। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र स्थित स्कीम नंबर 54 में एक दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। अलसुबह हेलमेट पहने बदमाश ने शटर का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने पास की एक गिफ्ट शॉप को भी निशाना बनाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।पुलिस के अनुसार, स्कीम नंबर 54 में राकेश व्यास की दुकान का शटर तोड़कर बदमाश ने दराज में रखे करीब 12 हजार रुपए और अन्य सामान चोरी कर लिया। वहीं, पास में स्थित विजय शिवहरे की 'सेलिब्रेशन गिफ्ट एंड टॉयज' दुकान का ताला तोड़कर करीब 4 हजार रुपए, परफ्यूम और अन्य सामान भी चुरा लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है।

केयरटेकर ने चुराई सोने की अंगूठी- एक अन्य मामले में पुलिस ने स्कीम नंबर 74 निवासी अखिल शर्मा की शिकायत पर ऋदम उर्फ सोनू (निवासी अमर टेकरी) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अखिल ने बताया कि उनके 95 वर्षीय दादा रामेश्वर, जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं, दवा लेकर सो गए थे। शाम को उठने पर उनके हाथ से सोने की अंगूठी गायब थी। घर में तलाश के दौरान पता चला कि केयरटेकर ऋदम भी काम पर नहीं आया। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

तेज रफ्तार कार ने बाइक-जीप को टक्कर मारी

एसआई-सिपाही सहित तीन घायल, टक्कर से पुलिस की गाड़ी पलटी

इंदौर (नप्र)। इंदौर के किशनगंज थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक सवारों को टक्कर मारी और फिर पुलिस की गश्ती गाड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में सब-इंस्पेक्टर सहित तीन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 15 अप्रैल को एबी रोड स्थित टीही पुलिया के आगे अज्ञात कार चालक तेज गति से गलत साइड में ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान उसने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गिरकर घायल हो गए। बाइक को टक्कर मारने के बाद भी कार चालक नहीं रुका और आगे जाकर पुलिस की गश्ती वाहन नंबर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पुलिस वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में पुलिस वाहन के सामने का कांच, दोनों गेट, बोनट, हेडलाइट, इंडिकेटर सहित इंजन को भारी नुकसान पहुंचा है। वाहन से ऑयल भी फैल गया। गश्त पर मौजूद सब-इंस्पेक्टर मुनेश यादव को कंधे, हाथ, पीठ और गर्दन में चोटें आईं।

घर में पड़ा रहा शव, चूहों ने कुतरा

आंख-चेहरा क्षत-विक्षत मिला; भांजे ने पुलिस-बेटों को सूचना दी; बच्चों की गेंद से खुला राज

इंदौर (नप्र)। इंदौर के चंदन नगर इलाके में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक का शव उसके घर में कई दिनों से पड़ा था। जिसे चूहों ने बुरी तरह कुतर दिया था। मृतक शराब पीने का आदी था। हैरानी की बात यह है कि घटना का खुलासा तब हुआ, जब गली में खेल रहे बच्चे गेंद लेने उसके घर के अंदर पहुंचे। शोर मचाने पर पड़ोसी वहां पहुंचे और मामले का पता चला। चंदन नगर पुलिस के अनुसार घटना नंदन नगर की है। यहां रहने वाले छगन नामक छगन (65) का शव उसके घर में लावारिस हालत में मिला। बुधवार शाम को बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे, तभी गेंद छगन के घर में चली गई। बच्चे जब गेंद लेने अंदर पहुंचे तो वहां शव पड़ा मिला और आसपास चूहे घूम रहे थे। इसके बाद तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि शव काफी समय से पड़ा होने के कारण चूहों ने आंखों, चेहरा सहित शरीर के कई हिस्सों को कुतर दिया था, जिससे शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया था। फिलहाल मौत के कारणों की जांच की जा रही है।

परिवार को खबर, फिर भी नहीं पहुंचे

मामले की जानकारी मिलने पर छगन के परिजनों को सूचित किया गया, लेकिन कोई मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में उसका भांजा गज्जू वहां आया और शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तीन बेटे, तीनों अलग रहते हैं- भांजे गज्जू ने बताया कि छगन के तीन बेटे हैं। उनकी शादी हो चुकी है। तीनों मजदूरी करते हैं। छगन की पत्नी की भी मौत हो चुकी है।

रोबोट चौराहे पर एसआई-ट्रेवल्स संचालक भिड़े, वीडियो वायरल

बस रोकने पर विवाद, पैसे मांगने और कॉलर पकड़ने के आरोप, डायल-112 पहुंची

इंदौर (नप्र)। इंदौर के खजराना इलाके स्थित रोबोट चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान एसआई और बस एजेंसी संचालक के बीच विवाद हो गया। बस खड़ी कर सवारी भरने को लेकर शुरू हुई बहस ने तूल पकड़ लिया। एजेंसी संचालक ने एसआई पर पैसे मांगने का आरोप लगाया, जबकि एसआई ने उल्टा उन पर अभद्रता और धक्का-मुक्की का आरोप लगाया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एसआई सुरेंद्र सिंह ने शिवानी ट्रेवल्स की बस को रोबोट चौराहे पर सवारी भरते समय रोका। इसी बात को लेकर एजेंसी संचालक सुनील चौहान (निवासी मेघदूत नगर) से उनकी बहस हो गई।

मौके पर सुनील का भतीजा यशराज भी मौजूद था। देखते ही देखते दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और आसपास लोग इकट्ठा हो गए।

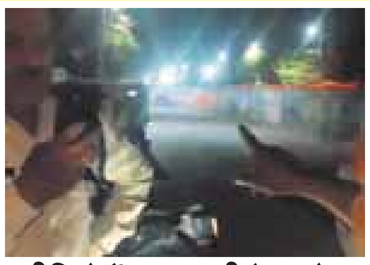

वीडियो में धक्का-मुक्की के आरोप

घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि एसआई सुरेंद्र सिंह ही पहले धक्का-मुक्की करते नजर आए। वहीं एसआई ने आरोप लगाया कि सुनील चौहान ने भीड़ के साथ मिलकर कॉलर पकड़ ली।इस दौरान एसआई ने खुद भी मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया और लोगों को चेतावनी देते दिखे।

डायल-112 बुलाकर दोनों को थाने ले गए- विवाद बढ़ने पर एसआई ने खजराना थाने पर सूचना दी और डायल-112 बुलाया। इसके बाद सुनील चौहान और उनके भतीजे को जबरन थाने ले जाया गया। देर रात पुलिस ने एसआई की शिकायत पर दोनों को थाने में बैठा लिया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उसी स्थान पर अन्य ट्रेवल्स की बसें भी रुकती हैं, लेकिन उन पर कभी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने एसआई पर कुछ बस संचालकों से सांठगांठ के आरोप भी लगाए हैं।

ट्रैफिक ड्यूटी को लेकर पहले भी उठे सवाल- सूत्रों के मुताबिक शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक ड्यूटी ठेके के आधार पर लगाने के आरोप पहले भी लग चुके हैं। इसे लेकर विभाग पर सवाल उठते रहे हैं और कई शिकायतें पुलिस कमिश्नर तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि वरिष्ठ अफसर हमेशा नियमपूर्वक ही ड्यूटी लगाने की बात करते आए हैं। हाल ही में लवकुश चौराहे से ट्रैफिक चौकी हटाई गई थी, जबकि अन्नपूर्णा क्षेत्र में भी लेनदेन के आरोप में दो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है।

इंदौर विकास प्राधिकरण में एनओसी रैकेट सक्रिय

योजना से जमीन मुक्त करने एक महीने में दो बार भेजी नकली एनओसी; अफसरों के हुए फर्जी साइन

इंदौर (नप्र)। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) में जमीन की एनओसी को लेकर एक बड़ा रैकेट चल रहा है। इसमें प्राधिकरण के ही कर्मचारी के मिले होने की बात सामने आई है। कर्मचारी खुद अधिकारियों के साइन कर एनओसी जारी करते हैं। इसके बाद टीएनसीपी में नक्शा मंजूरी के लिए भेजा जा रहा था। यह खुलासा टीएनसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) अधिकारियों की जांच से हुआ है। इधर, आईडीए अधिकारियों का शक है कि विधि विभाग का बाबू शुभम श्रीवास्तव इस रैकेट से जुड़ा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि जिस दिन से मामला सामने आया है, उस दिन से ही वह बिना सूचना के ऑफिस नहीं आया है। उसका फोन भी बंद है। घर से भी लापता है।

एनओसी और प्रारूप में साइन का अंतर- मामला योजना 97 पार्ट 4 बिजलपुर की जमीन का है। करीब 20 हजार वर्गफुट से ज्यादा यह जमीन आईडीए की योजना में शामिल है। हाल ही में जमीन मालिक की ओर से टीएनसीपी के समक्ष ले-आउट स्वीकृति के लिए आवेदन किया था। दस्तावेज परीक्षण में पता चला कि आईडीए से जारी की गई एनओसी और प्रारूप में

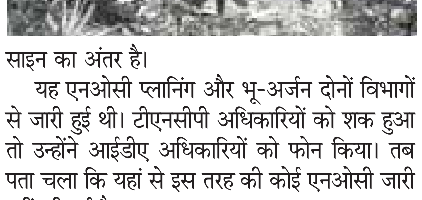

साइन का अंतर है।

यह एनओसी प्लानिंग और भू-अर्जन दोनों विभागों से जारी हुई थी। टीएनसीपी अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने आईडीए अधिकारियों को फोन किया। तब पता चला कि यहां से इस तरह की कोई एनओसी जारी नहीं की गई है।

1.5 महीने पहले पहली बार भेजी गई फर्जी एनओसी- टीएनसीपी अधिकारी शुभाशीष बनर्जी ने बताया कि हमारे पास उस जमीन का नक्शा मंजूरी के लिए फाइल आई थी। हमने एनओसी मांगी तो उन्होंने एनओसी में बताया कि यह जमीन आईडीए की स्कीम में नहीं है। हमें एनओसी पर कुछ साइन ऐसे लगे कि वह गलत हैं। हमने फोन कर पूछा कि जमीन की एनओसी हमारे पास आई है। इस पर आईडीए अधिकारी ने कहा कि हमारे यहां से जारी नहीं हुई है। यह पता चलने पर हमने उसे कैंसिल कर दिया। 4 से 5 दिन पहले फिर हमारे पास यह फाइल आई, तब हमें दोबारा शक हुआ। हमने आईडीए को एनओसी की फोटो कॉपी भेजकर पूछा कि इसकी पुष्टि करें कि यह आपके यहां से जारी हुई है या नहीं। इस पर आईडीए ने फिर से एनओसी जारी करने से मना कर दिया।

आईडीए अधिकारी के किए नकली साइन- भू-अर्जन अधिकारी सुदीप मीणा ने बताया कि नकली साइन कर फर्जी एनओसी बनाने का मामला हमारे सामने आया है। मेरे भी नकली साइन बनाकर फर्जी एनओसी बनाई गई है। मेरे से पहले कंट्री प्लानिंग के अधिकारी के साइन किए गए थे।अब ऑनलाइन होगा पूरा एनओसी सिस्टम आईडीए सीईओ परीक्षित झाड़े का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर मामले की जांच करवाई जा रही है। मामला जिस योजना का है, उसके बारे में प्राधिकरण ने पहले विभाग को एनओसी की तस्दीक करने के बाद ही ले-आउट स्वीकृत करने के लिए कहा है। फर्जी एनओसी की शिकायतों को देखते हुए अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। मामले की विभागीय जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।

बढ़ सकता है जांच का दायरा- इस खुलासे के बाद अब प्राधिकरण प्रशासन पुरानी जारी की गई एनओसी फाइलों को भी खंगालने की योजना बना रहा है। अंदेशा जताया जा रहा है कि इस रैकेट ने पहले भी कई अन्य जमीनों के मामलों में इसी तरह की फर्जी एनओसी जारी कर शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया हो सकता है। सूत्रों के अनुसार यह रैकेट पिछले एक साल से चल रहा है। इसमें शामिल लोग जमीन की कीमत के अनुसार रेट तय कर एनओसी बनाते थे।

जमीन की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा- आईडीए सूत्रों ने बताया कि जिस जमीन को लेकर दो बार नकली साइन करके एनओसी जारी की गई है, उस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आईडीए की जांच में शिवम के अलावा विभाग के दो और कर्मचारी के शामिल होने का शक है।

संपादकीय

परिसीमन विधेयक: विपक्ष उलझन में

मोदी सरकार द्वारा देश में पांच राज्यों में चली रही चुनाव प्रक्रिया के बीच अचानक परिसीमन विधेयक लाने और देश में राज्यों की लोकसभा सीटों को बढ़ाकर डेढ़ गुना करने ताकि महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके, का भाजपा और एनडीए को कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा, कहना मुश्किल है, लेकिन इसने समूचे विपक्ष को भारी उलझन में डाल दिया है कि वह बिल का खुलकर समर्थन करे अथवा विरोध? संसद में इस पर तीखी बहस होना तय है और सड़कों पर तो विपक्षी पार्टियों का अभी से शुरू हो गया है। कांग्रेस इसे ' हिस्सा चोरी' तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस बिल को जलाकर और काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जता दिया है। गौरतलब है कि इस बिल में लोकसभा में सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने तथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का भी प्रस्ताव है। महिला आरक्षण का ये प्रस्ताव 2023 में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर आधारित हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन इसके लागू होने को भविष्य में होने वाली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया था। नए प्रस्ताव के मुताबिक़ लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने के बाद महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के मुताबिक सरकार डीलिमिटेशन प्रक्रिया के तहत उत्तर भारत और जिन राज्यों में वो मज़बूत है, वहां सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है। इससे उत्तर और दक्षिण भारतीय राज्यों में सीटों का फ़ासला बहुत बढ़ जाएगा, जो भाजपा को ही फ़ायदा पहुंचाएगा। इससे दक्षिण भारतीय राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कमज़ोर होगा। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा इन आरोपों का खंडन करते हुए कह रही है कि सभी परिसीमन के बाद राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा और महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित करके वो उनकी भागीदारी को बढ़ाना चाहती है। लेकिन विपक्ष को इस पर भरोसा नहीं हो रहा। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे बीजेपी का 'खतरनाक खेल' बताते हुए कि वह 2029 के चुनावों में अपने फ़ायदे के लिए सभी लोकसभा सीटों की सीमांकन प्रक्रिया अपने हिसाब से करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक सारी शक्ति डीलिमिटेशन कमीशन को सौंप देंगे जिसे सरकार खुद नियुक्त और निर्देशित करेगी। असम और जम्मू कश्मीर में ऐसा ही किया गया। उन्होंने कहा कि हम मोदी सरकार को ओबीसी, दलित और आदिवासियों से हिस्सा चोरी नहीं करने देंगे। सरकार जाति जनगणना के आंकड़ों की अनदेखी करना चाहती है। हम दक्षिणी, पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों के साथ नाइंसाफ़ी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार जो प्रस्ताव ला रही है, उसका महिला आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हटकर देखें तो बीच चुनाव में यह बिल लाने की क्या इमरजेंसी थी, यह किसी की समझ नहीं आ रहा। हालांकि पांच में से तीन राज्यों में वोट पड़ चुके हैं। तमिलनाडु में भाजपा के लिए कोई संभावना नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो इस विधेयक का राजनीतिक लाभ लेना चाहेगी। कितना मिलेगा, यह अलग बात है। लेकिन तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर लगातार भाजपा पर हमला करने वाली ममता बैनर्जी की तोप अब परिसीमन की तरफ मुड़ गई है। चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए इसे पास कराने के लिए सदन की उपस्थित सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत यानी 360 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। जबकि विपक्ष विरोध में वोट करने का मन बना चुका है। ऐसे में यह विधेयक पारित होगा या सिलेक्ट कमेटी को जाएगा, यह देखने की बात है।

जोड़ने के लिए जाने जाएंगे चंद्रशेखर

नजरिया

अरुण कुमार त्रिपाठी

लेखक मीडिया शिक्षक हैं।

चंद्रशेखर (पूर्व प्रधानमंत्री) जब सन् 1964 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे थे तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि वे कांग्रेस पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं तो उनका कहना था कि मैं इसे समाजवादी बनाना चाहता हूं। इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर समाजवादी नहीं बना पाए तो क्या करोगे, इस पर चंद्रशेखर का जवाब था कि मैं उसे तोड़ दूंगा। लेकिन अपने पांच दशक के राजनीतिक कार्यकाल में चंद्रशेखर अगर किसी कार्य या प्रयास के लिए सर्वाधिक जाने जाएंगे तो वह तोड़ने नहीं जोड़ने के लिए। निश्चित तौर पर 1969 में जब बंगलूर अधिवेशन के बाद कांग्रेस पार्टी टूटी तो उस अधिवेशन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए जो दस सूत्री समाजवादी प्रस्ताव पेश किए गए उसे तैयार करने में चंद्रशेखर की बड़ी भूमिका थी। जिसके तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने और राजाओं के प्रीवी पर्स छीने जाने जैसे कई रेडिकल कदम उठाए गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जन्मशती पर उन्हें स्मरण करने के कई कारणों में सबसे बड़ा कारण यही है कि वे समाजवाद के रेडिकल सुधारों से अधिक समाज के साझेपन के ताने बाने को बचाने के लिए याद किए जाएंगे। चंद्रशेखर, चंद्रजीत यादव, रामधन, मोहन धारिया और दूसरे साथियों के साथ लगभग एक दशक तक कांग्रेस के युवा तुर्क कहे जाते थे। तुर्की में 1908 में क्रांतिकारी पार्टी के सदस्यों के लिए प्रयोग होने वाले इस विशेषण का तात्पर्य उनसे था, जिन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद की सत्ता को पलट दिया था। भारत में वे लोग मोरारजी देसाई जैसे कांग्रेस के बूढ़े पूंजीवाद समर्थक नेताओं की जगह पर इंदिरा गांधी जैसी युवा नेत्री और समाजवादी सदस्यों को आगे लाने के पक्षधर थे। इन्हीं नीतियों पर चलकर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति पद के कांग्रेस के अधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को हराकर वीवी गिरि को जितवाया था। लेकिन कभी समाजवाद के लिए कांग्रेस को तोड़ने वाले चंद्रशेखर ने जरूरत पड़ने पर कांग्रेस के टूटे धड़े और जनसंघ और देश के दूसरे दलों को एक साथ जोड़ने में संकोच नहीं किया। जब चंद्रशेखर को परिवर्तनकारी क्रांतिकारी धारा इंदिरा गांधी के कांग्रेस के बजाय जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में दिखी तो वे उससे जुड़ गए।

हालांकि चंद्रशेखर इस कोशिश में थे कि इंदिरा गांधी और जेपी के बीच कोई समझौता करा सकें। इस बारे में उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा भी है। लेकिन जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख, रामनाथ गोयनका और दूसरे लोग इस कोशिश में लगे थे कि ऐसा कोई समझौता न हो पाए। इन लोगों ने इंदिरा गांधी के उस पत्र का अवमानना वाला अर्थ निकाला जो जेपी को बिहार आंदोलन के बारे में लिखा गया था। स्थितियां टकराव की ओर गईं और आपातकाल लगा। तब चंद्रशेखर ने सरकार के साथ रहने के बजाय जेल जाने का विकल्प चुना। जेपी से मिलने गए चंद्रशेखर को मीसा के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। वे आपातकाल के 19 महीने रोहतक, चंडीगढ़ और पटियाला के जेलों में रखे गए। इस दौरान चंद्रशेखर ने स्वाधीनता संघर्ष की परंपरा का निर्वाह करते हुए इन जेलों की पूरी लाइब्रेरी खंगाल डाली। उन्होंने विपुल विश्व साहित्य का विषद अध्ययन किया। दुनिया भर के क्रांतिकारियों का साक्षात्कार किया। इसका वर्णन उनकी जेल डायरी में मिलता है। चंद्रशेखर की प्रतिभा और प्रतिबद्धता को देखते हुए ही जयप्रकाश नारायण ने उन्हें उस जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जिस पर आपातकाल की अंधेरी कोठरी से निकली दूसरी आजादी की हिफाजत की जिम्मेदारी थी। जेपी ने किसी प्रकार दबाव डालकर विपक्ष के विभिन्न दलों को एकजुट करके चुनाव तो जितवा दिया था और जनता सरकार का गठन भी करा दिया था, लेकिन सबसे कठिन काम था उन्हें एक रखना। इस मार्ग में नेताओं की निजी महत्वाकांक्षा तो चुनौती थी ही लेकिन उससे बड़ी चुनौती थी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जनसंघ की दोहरी सदस्यता। संघ के नेता बाला साहेब देवरस ने जेपी को आश्वासन दिया था कि वे सांप्रदायिक राजनीति छोड़ देंगे। इधर जनसंघ के तमाम नेताओं ने जनता पार्टी में शामिल होने के साथ उस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कि वे संघ के दैनंदिन कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे और उससे किनारा कर लेंगे। यही शर्त थी जनसंघ को जनता पार्टी में पूरी तरह विलय करने की। इस काम में चंद्रशेखर लगे और उनके साथ राजनारायण भी थे। लेकिन हमेशा की तरह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपना वचन भंग किया।संघ की प्रतिनिधि सभा ने उस प्रस्ताव को अनुमोदित करने से मना कर दिया। चंद्रशेखर लिखते हैं, 'मुझे उम्मीद थी कि देवरस अपना वह वचन निभाएंगे। लेकिन मुझे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चरित्र पर हैरानी नहीं हुई। '

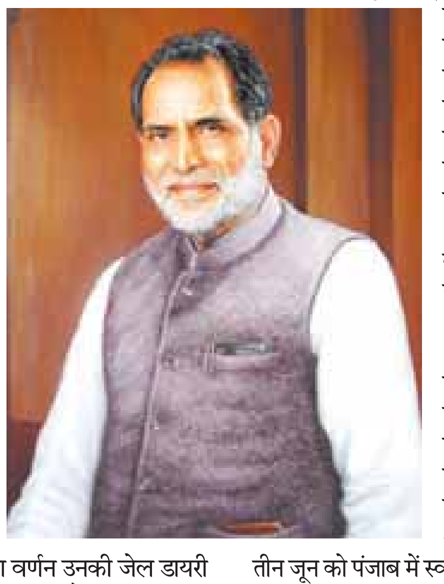

जनता पार्टी टूटने और सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर अपने भाषणों में यही कहते घूमते थे कि मैं जहाज का कप्तान था। मुझे मालूम था कि जहाज डूब रहा है लेकिन मैं कैसे भागता। आखिर तक डटा रहा। उन घटनाओं से चंद्रशेखर दुखी हुए लेकिन निराश नहीं हुए। उन्हें भारत के जनगण की आंतरिक शक्ति पर गहरा भरोसा था। वे उनसे प्रेरणा पाने और उसे जगाने के लिए 1983 के आरंभ में ही कन्याकुमारी से राजघाट तक की यात्रा पर निकल पड़े। तकरीबन 4260 किलोमीटर की यह यात्रा 6 जनवरी को शुरू होकर 25 जून को आपातकाल की वरसी पर राजघाट पर पूरी हुई। यात्रा में उन्होंने न सिर्फ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया बल्कि देश के तमाम मसलों पर खुलकर अपनी बात रखी। इसी दौरान तीन जून को पंजाब में स्वर्ण मंदिर पर आपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई हुई जिसका चंद्रशेखर ने स्पष्ट शब्दों में विरोध किया और कहा कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनकी बात सच निकली और 31 अक्तूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई।

अस्सी का दशक भारत में सांप्रदायिक राजनीति के मजबूत होने और हिंसक होने की शुरुआत थी। यही दौर था उन राजनीतिक समझौतों और सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के प्रयास तीव्र हो गए थे जिन पर भारत टिका था। संघ परिवार की अखिल भारतीय एकात्मकता यात्रा और पूना समझौते के विरुद्ध कांशीराम की पूना से दिल्ली तक की यात्रा भी इसी समय हुई। चंद्रशेखर इस विभाजनकारी राजनीति से लड़ने के लिए अपनी शक्ति जुटा रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद था वह कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। चंद्रशेखर बलिया से चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि खालिस्तान बलिया में ही बनने वाला है।

चंद्रशेखर जाति और धर्म के आधार पर देश के राजनीतिक ध्रुवीकरण के कायल नहीं थे। वे आजीवन मार्क्सवादी रहे आचार्य नरेंद्र देव के शिष्य थे और जयप्रकाश नारायण में उन्होंने परिवर्तनकारी लोकतांत्रिक राजनीति का सार्थवाह देखा था। इसलिए एक अलग राजनीतिक धारा विकसित करने में लगे थे जो लोकतांत्रिक भी हो और परिवर्तनकारी भी और जिसमें न सांप्रदायिक जहर हो और न जातिवादी। लेकिन सामने उठते झंझावात की दिशा उन्होंने पहचान ली थी और आखिरी चरण में उन्होंने अपनी भूमिका महज एक फायरब्रिगेड के रूप में देखी। जैसा कि कभी आइंस्टीन ने युद्ध के खतरों को देखते हुए कहा था कि समाजवाद से अधिक शांति कायम करना जरूरी है वैसा ही शायद चंद्रशेखर ने भी सोचा। जब वे वीपी सिंह को हटाकर प्रधानमंत्री बने और बीमार वीपी सिंह को अस्पताल में देखने गए तो उन्होंने कहा कि आप अपनी तबियत का ध्यान रखिए, क्योंकि आप ने देश को जहां पहुंचा दिया है वहां से वह जल्दी स्वस्थ होने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर वीपी सिंह के कार्यकाल में मंदिर-मस्जिद का विवाद और मंडल आयोग पर हुआ ध्रुवीकरण जिस हद तक पहुंचा उसे देश आज तक झेल रहा है। चंद्रशेखर ने अपने कार्यकाल में उस आग पर पानी डालने का काम किया।

चंद्रशेखर ने पंजाब समस्या के समाधान का प्रयास किया और अयोध्या के बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि के विवाद का भी हल निकालना चाहा। महज चार माह के प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने दोनों पक्षों को समाधान के करीब ला भी दिया था। लेकिन आडवाणी ने अशोक सिंघल से कहा कि उन्हें मंदिर थोड़े ही बनाना है उन्हें तो दिल्ली में सरकार बनानी है। बाद में चंद्रशेखर को लगा कि समस्याओं की जड़ में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां हैं। वे उसके विरुद्ध उड़ीसा से गुजरात तक की यात्रा पर भी निकले। चंद्रशेखर सचमुच भारतीय राजनीति के अजातशत्रु थे। सबसे संवाद और सबको खरी-खरी। लोहिया के शब्दों में कहें तो उनकी आंखों में एक ओर केरल तो दूसरी ओर त्रिपुरा रहता था। बलिया जिले के इब्राहीम पट्टी के गरीब किसान परिवार के इस बेटे पर कवि अवध बिहारी की कविता खूब फबती है:–

बालक ओ नंगे पांव का।
बलिया के पिछड़े गांव का।।
गमछे में दाना खा रहा।
स्कूल पैदल जा रहा।।

हालांकि चंद्रशेखर ने अपनी गरीबी का न तो कभी गौरवगान किया और न ही उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया। उनकी खूबी थी राष्ट्र निर्माण की साहसिक दृष्टि के साथ गंवई स्पष्टवादिता। लेकिन चंद्रशेखर को किसी मजबूत राजनीतिक संगठन की कमी सदैव सालती रही। यही वजह थी कि समन्वयवादी परिवर्तन का यह राजनीतिज्ञ देश की नफरती खाइयों को पाटने में खो गया।

राजनीति

जयदेव राठी

लेखक अधिवक्ता हैं।

नया सम्राट, पुरानी समस्याएँ, क्या बदलेगा बिहार का भाग्य?

बिहार की राजनीतिक धरती ने एक बार फिर इतिहास रचा है। लगभग दो दशक तक बिहार की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा विधायक दल ने सम्राट चौधरी को अपना नेता चुना। सम्राट चौधरी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री होंगे, नवंबर 2025 के अभूतपूर्व चुनावी परिणाम में भाजपा बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। मुंगेर की माटी से आने वाले 57 वर्षीय सम्राट चौधरी का राजनैतिक कद रातों-रात नहीं बढ़ा – उनके पिता शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापकों में से एक और लालू प्रसाद यादव के निकट सहयोगी रहे थे। सम्राट की राजनीतिक यात्रा राजद से प्रारंभ होकर जेडीयू और फिर 2018 में भाजपा तक पहुँची। तारापुर की माटी से उठे इस नेता के कंधों पर अब बिहार की 13 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का बोझ है। राज्याभिषेक तो हो गया – किंतु असली प्रश्न यह है कि क्या सम्राट, बिहार की उन पुरानी और गहरी समस्याओं से पार पा सकेंगे जो दशकों से राज्य को पिछड़ेपन की जंजीरों में जकड़े हुए हैं?

नीतीश कुमार का मूल्यांकन कितना ही विवादास्पद हो, एक तथ्य निर्विवाद है – उन्होंने बिहार को लालू-राबड़ी के जंगलराज से निकालकर सुशासन की एक आधारभूमि दी। सड़कें बनीं, बिजली पहुँची, महिला सशक्तीकरण के कार्यक्रम चले। किंतु उनके दो दशक के शासन का सबसे बड़ा अधूरापन यह रहा कि बिहार आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में उस गति से नहीं दौड़ सका, जिसकी उसे दरकार थी। शिक्षा, रोजगार और औद्योगिक विकास – इन तीन मोर्चों पर बिहार आज भी राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है। सम्राट चौधरी को यह विरासत संभालनी है – और इसमें न केवल पुराने घाव भरने हैं, बल्कि नए संकल्पों का बीजारोपण भी करना है।

बिहार की राजनीति में शराबबंदी एक ऐसा प्रश्न है जो हर दल को असहज करता है। यह फैसला सामाजिक दृष्टि से साहसिक तो है, किंतु राजस्व की दृष्टि से जोखिम भरा है – राज्य सरकार को इससे हर साल 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होता है। कुछ अर्थशास्त्री तो इससे भी बड़ी क्षति का आकलन करते है। आकडों के अनुसार 9 वर्षों में राज्य को एक लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और औसतन हर साल 12,000 करोड़ की राजस्व क्षति होती रही है। दूसरी ओर, लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित एक शोध यह दर्शाता है कि 2016 में लागू शराबबंदी से 24 लाख से अधिक मामलों में शराब-सेवन और 21 लाख से अधिक मामलों में घरेलू हिंसा पर नियंत्रण हुआ। यह आँकड़े यह भी सिद्ध करते हैं कि शराबबंदी के सामाजिक लाभ नगण्य नहीं हैं। किंतु समस्या यह है कि शराबबंदी कागज़ों पर तो लागू है, व्यवहार में नहीं। अवैध शराब का कारोबार फला-फूला, ज़हरीली शराब से मौतें हुईं, और भ्रष्टाचार का एक नया पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो गया। सम्राट चौधरी के सामने यह कठिन विकल्प है – या तो शराबबंदी को वास्तव में क्रियान्वित करें, या इसकी नीतिगत समीक्षा का साहस दिखाएँ। भाजपा के लिए यह विषय और भी संवेदनशील है क्योंकि महिला वोट बैंक इससे सीधे जुड़ा है। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने भी बिहार में शराबबंदी के जल्द समाप्त होने और आर्थिक संकट की आशंका जताई है । निर्णय जो भी हो – उसके दूरगामी परिणाम होंगे

बिहार की सबसे मर्मांतक पीड़ा उसके श्रमिकों का पलायन है। दिल्ली की निर्माण-स्थलों पर, मुंबई के कारखानों में, पंजाब और हरियाणा के खेतों में – बिहार का युवा दिहाड़ी मज़दूर बनकर काम करता है। यह पलायन केवल आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षय का भी प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष लाखों बिहारी अपना घर-परिवार छोड़कर रोज़ी-रोटी की खोज में निकलते हैं। इस पलायन को रोकने का एकमात्र उपाय है – बिहार में उद्योग, और उद्योग के लिए चाहिए बुनियादी ढाँचा, बिजली की निर्बाध आपूर्ति, कानून-व्यवस्था, और निवेशकों का विश्वास। नीतीश शासन में कुछ प्रयास हुए – इन्वेस्टर्स समिट आयोजित हुए, घोषणाएँ हुईं – किंतु धरातल पर बड़े उद्योग नहीं आए। बिहार में न बंदरगाह है, न समतल भूमि का बड़ा विस्तार उद्योग के लिए उपयुक्त। बाढ़ की वार्षिक विभीषिका अलग है। सम्राट चौधरी को यह समझना होगा कि केवल घोषणाओं से पलायन नहीं रुकता – एक विश्वसनीय औद्योगिक नीति, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन, और कृषि-आधारित उद्योगों का विकास ही इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान है।

बिहार का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था की नींव पर टिका है – और यह नींव अभी भी खोखली है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, भवनों का जर्जर होना, मध्याह्न भोजन में अनियमितता, और उच्च शिक्षा के गुणवत्ताहीन संस्थान – ये सब मिलकर बिहारी युवा को पहले दिन से पिछड़ेपन की ओर धकेलते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार के युवाओं की उपस्थिति उनकी जिजीविषा का प्रमाण है – किंतु यही युवा जब उचित शिक्षा-सुविधाओं से वंचित रहते हैं, तो यह राज्य की नहीं, पूरे देश की क्षति है। सम्राट चौधरी के लिए यह आवश्यक होगा कि वे शिक्षा को केवल योजनाओं में नहीं, प्राथमिकता के धरातल पर रखें। नालंदा और विक्रमशिला की धरती पर जहाँ कभी विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानकेंद्र था, वहाँ आज की पीढ़ी को उस गौरव की पुनः प्राप्ति करानी है। इसके लिए चाहिए शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता, तकनीकी शिक्षा का विस्तार, और निजी क्षेत्र की भागीदारी। बिहार को आज भी देश के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। स्वास्थ्य सुविधाएँ दयनीय हैं। बाढ़ और सूखे का चक्र कृषि को तबाह करता रहता है। इस पिछड़ेपन का कलंक मिटाना केवल संख्याओं का खेल नहीं – यह जन-मानस में आत्मविश्वास की पुर्नस्थापना का प्रश्न है। बिहार की राजनीति, जो अपनी अनिश्चितता और अप्रत्याशित मोड़ों के लिए जानी जाती है, ने इस ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ एक नया अध्याय खोला है। भाजपा के लिए बिहार अब केवल गठबंधन-धर्म का मैदान नहीं – यह उसकी शासन-क्षमता की वास्तविक परीक्षा है। सम्राट चौधरी को यह सिद्ध करना होगा कि भाजपा केवल सत्ता पाना जानती है, शासन चलाना भी जानती है। 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में सबसे कम उम्र के कृषि मंत्री बने सम्राट की राजनीतिक परिपक्वता और विभिन्न दलों में काम करने का अनुभव उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण देता है। यह अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूँजी है। किंतु बिहार की समस्याएँ व्यक्तिगत अनुभव से नहीं, नीतिगत साहस से हल होती हैं।

बिहार को एक ऐसे नेतृत्व की प्रतीक्षा है जो न केवल जंगलराज की स्मृति मिटाए, बल्कि विकास-राज की ऐसी इबारत लिखे जिसे आने वाली पीढ़ियाँ याद रखें। सम्राट चौधरी के सामने यह सुनहरा अवसर है, और यही सबसे कठिन परीक्षा भी। बिहार की जनता ने भाजपा को पहली बार सीधे सत्ता सौंपी है। यह विश्वास का मत है। इस विश्वास को यदि नीतियों में नहीं बदला गया, तो बिहार का मतदाता, जो राजनीतिक रूप से भारत का सर्वाधिक जागरूक मतदाता माना जाता है, अगली बार अपना हिसाब अवश्य माँगेगा।

'लाल स्वर्ण' के विजेता

कटाक्ष

गोविन्द सेन

लेखक व्यंग्यकार हैं।

आज के दौर में शांतिकी तलाश हिमालय की कंदराओं में नहीं, बल्कि गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर खड़ी भीड़ में होती है। वह जमाना गया जब लोग सुबह उठकर सूरज को अर्घ्य देते थे, आज का आधुनिक मानव सुबह उठकर सबसे पहले लाल रंग के उस लोहे के देवतुल्य पात्र को हिलाकर देखता है जिसे दुनिया गैस सिलेंडरके नाम से जानती है। अगर वह हल्का निकला, तो समझ लीजिए उस घर में शोक की लहरदौड़ गई है। समझो कि तोता उड़ गया है, केवल पिंजरा रह गया है।

गैस सिलेंडर की मारामारी दरअसल एक आधुनिक युद्ध है, जिसमें हथियार तलवारें नहीं, बल्कि कन्फर्मेशन मैसेजऔर बुकिंग आईडीहोते हैं। जैसे ही घर की रसोई से यह घोषणा होती है कि 'जी, सिलेंडर जवाब दे गया है, 'घर का मुखिया अचानक से किसी जासूस या कमांडो की मुद्रा में आ जाता है। उसका पहला काम होता है एजेंसी को फोन करना, जहाँ से जवाब आता है– 'अभी स्टॉक नहीं है, दो दिन बाद आना।' यह सुनते ही मुखिया के चेहरे के भाव वैसे ही हो जाते हैं जैसे किसी ने उसकी पैतृक संपत्ति हड़प ली हो।

एजेंसी के बाहर का नजारा तो किसी कुंभ के मेले से कम नहीं होता। वहाँ खड़े लोग एक-दूसरे को ऐसे शक की निगाह से देखते हैं जैसे सामने वाला उनका सिलेंडर चुराने आया हो। लाइन में खड़े हर व्यक्ति की अपनी रणनीति होती है। कोई फोन पर झूठ बोल रहा होता है- 'बस पाँच मिनट में सिलेंडर लेकर दफ्तर पहुँच रहा हूँ, 'तो कोई अपनी बारी आने पर हॉकर से ऐसे लिपट जाता है जैसे बरसों पुराना बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो।

सिलेंडर पाने की इस जद्दोजहद में जुगाड़का बड़ा महत्व है। जिसके पास एजेंसी के मैनेजर का नंबर है, वह मोहल्ले का अघोषित डॉन कहलाता है। लोग उससे ऐसे गुहार लगाते हैं जैसे वह कोई साक्षात वरदान देने वाला देवता हो। 'भाई साहब, बस एक लाल डब्बा दिलवा दो, बिटिया की सगाई का खाना बनना है, 'जैसे जुमले आम हैं, भले ही बिटिया अभी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रही हो।

विडंबना देखिए, जिस सिलेंडर को हम घर में बमसमझकर डरते थे, आज उसे पाने के लिए लोग बम की तरह फटने को तैयार रहते हैं। जब सिलेंडर घर आता है, तो उसका स्वागत किसी नवविवाहित वधू की तरह होता है। उसे बड़े जतन से पोंछकर, सिर पर उठाकर या गाड़ी पर बाँधकर ऐसे लाया जाता है जैसे कोई युद्ध जीत कर लौटा हो। पड़ोसी भी खिड़की से झाँककर ईर्ष्या भरी नजरों से देखते हैं और बुदबुदाते हैं– 'इनका तो हमेशा जुगाड़ फिट रहता है।'

इस मारामारी ने इंसान को धैर्य की पराकाष्ठा सिखा दी है। खाली सिलेंडर के ऊपर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना, आज के युग का सबसे बड़ा योगहै। इस योग को 'सिलेंडर योग' कह सकते हैं। अंत में, जब चूल्हा जलता है और पहली रोटी फूलती है, तब जाकर उस योद्धा को सुकून मिलता है जिसने घंटों धूप में खड़े होकर 'लाल स्वर्ण' यानी गैस सिलेंडर प्राप्त किया होता है। जीवन में मोक्ष मिले न मिले, लेकिन समय पर गैस सिलेंडर मिल जाए, तो समझो गंगा नहा लिए!

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल

संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी

स्थानीय संपादक
हेमंत पाल

प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

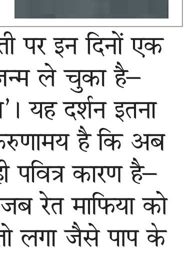

सुदर्शन सोनी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

पेट माफिया: जब अपराध पेट पूजा बन गया

चंबल की धरती पर इन दिनों एक नया दर्शन जन्म ले चुका है– 'पेट माफिया'। यह दर्शन इतना उदार और करुणामय है कि अब हर अपराध का एक ही पवित्र कारण है– पेट। एक मंत्री जी ने जब रेत माफिया को 'पेट माफिया' कहा, तो लगा जैसे पाप के घड़े में गंगाजल उलीचकर उसे पुण्य साबित करने की कोशिश हो रही हो। पर सच्चाई यह है कि पाप में गंगाजल मिलाने से वह पुण्य नहीं बनता, बस घड़ा भरकर फूटने का इंतजार करता है।

मुरैना में हाल ही में एक वनरक्षक को ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचल दिया गया। वह डंडे और हौसले के सहारे कानून का पालन कराने निकला था, लेकिन सामने 'पेट' था–और पेट के आगे कानून हमेशा दुबला पड़ जाता है। किताबों में मोटा-तगड़ा दिखने वाला कानून जमीन पर इन कथित 'पेटों' के सामने कुपोषित नजर आता है, खासकर तब जब ये पेट राजनैतिक संरक्षण रूपी गर्भनाल से से जुड़ आवश्यक पोषण प्राप्त कर रहे हों। अब असली सवाल यह है कि उस वनरक्षक के परिवार का पेट कौन भरेगा? उसकी पत्नी और छोटे बच्चों की भूख किस 'पेट दर्शन' से शांत होगी? या फिर उनका दर्द 'गैर-जरूरी भूख' की श्रेणी में डाल दिया जाएगा?

दरअसल, 'पेट माफिया' एक जादुई शब्द बन चुका है, जो अपराध को संस्कार में बदल देता है। आज रेत माफिया 'पेट माफिया' है, तो कल शराब माफिया 'पेट पोषण योजना' के ब्रांड एंबेसडर बन जाएंगे। अगर हर अवैधता को पेट की वैधता से जोड़ दिया गया, तो वेश्यावृत्ति 'पेट सेवा' और ड्रग्स बेचने वाले 'पेट के कीमियागर' कहलाएंगे। फिर अपराधी नहीं होंगे–सिर्फ 'पेट के शोधकर्ता' होंगे, जो अवैध कमाई के नए-नए प्रयोग कर रहे हैं।

इस पूरे खेल में सबसे बड़ा मजाक मैदानी वन अमले के साथ हो रहा है। उनके पास डंडा है, सामने बंदूकधारी 'पेट रक्षक'। यह मुकाबला ऐसा है जैसे महाभारत में अर्जुन को खिलौना धनुष थमा दिया जाए। यदि कोई वनकर्मी आत्मरक्षा में गोली चला दे, तो ऐसा हंगामा होता है मानो कानून खतरे में पड़ गया हो। नतीजा–वनकर्मियों की बंदूकें थानों में जमा हो उनके हाथ बंद पर, अपराधियों के हाथ खुले। ऐसा लगता है जैसे वनरक्षक जंगल नहीं, किसी 'अहिंसा आश्रम' में ड्यूटी कर रहा हो, जहां उसे पेड़ भी बचाने हैं और अपनी जान भी–वो भी सिर्फ डंडे के सहारे।

'पेट माफिया' सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब अपराधी और नेता के बीच की दूरी लगभग खत्म हो गई है। दोनों ही पेट के नाम पर काम कर रहे हैं–एक कानून को कुचलकर पेट भरता है, दूसरा तर्क और सच्चाई को कुचलकर उसका बचाव करता है।

जरूरत इस बात की है कि 'पेट' को ढाल बनाकर अपराध को वैध ठहराने की इस प्रवृत्ति पर तुरंत रोक लगे। वरना कल हत्या भी 'पेट रक्षा अभियान' बन जाएगी। जब शब्दों की धुलाई से अपराध चमकने लगे, तो समझ लीजिए व्यवस्था का रोकथाम का साबुन ही नकली है।

अंततः सवाल वही गूंजता है–इस 'पेट माफिया' को संरक्षण कौन दे रहा है? क्योंकि जैसे ही अपराध को भूख का प्रमाणपत्र मिला, उसने कानून के शासन का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। मुरैना की घटना कोई अपवाद नहीं, बल्कि उस श्रृंखला की एक और कड़ी है, जहां 'हाथ कंगन को आरसी क्या' की तरह सच्चाई बार-बार सामने आ रही है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम
धर्मेन्द्र सिंह लोधी
राज्यमंत्री, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

सशक्त सहभागिता और समावेशी भविष्य की आधारशिला

स्त्रियों को देवताओं और रत्नों के समान माना जाता है। स्त्रियाँ सर्वदा महान होती हैं। संसार में स्त्री से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। इसी मूल भावना का समावेश भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी किया गया है। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा नारी जाति के प्रति समानता, सहभागिता और प्रतिनिधित्व में निहित है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' इसी पुनीत भावना का सशक्त प्रतिपादन है। यह अधिनियम एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है, जो भारतीय राजनीति, समाज और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका को न केवल स्वीकार करता है, बल्कि उसे संस्थागत आधार भी प्रदान करता है।

मानव सभ्यता का उत्कर्ष, अस्तित्व, विकास और उसका गतिमान चरित्र दो स्तंभों पर टिका है- एक स्त्री और दूसरा पुरुष। वास्तव में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और इसी रूप में मानव जीवन की सार्थकता है। निर्विवाद रूप से मानव जाति का उत्कर्ष और अस्तित्व नारी जाति की सृजनशीलता पर आधारित है। अपने सृजनशील गुण के कारण ही भारत की महान सनातन संस्कृति में स्त्री को पूजनीय और वंदनीय माना गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं -

स्त्रीणां देवत्वं रत्नेषु च, योषितत्वं महतसदा।
न स्त्रीणामधिकं किंचित्, पवित्रं जगति क्वचित।।

अर्थात, स्त्रियों को देवताओं और रत्नों के समान माना जाता है। स्त्रियाँ सर्वदा महान होती हैं। संसार में स्त्री से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है।

इसी मूल भावना का समावेश भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी किया गया है। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा नारी जाति के प्रति समानता, सहभागिता और प्रतिनिधित्व में निहित है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' इसी पुनीत भावना का सशक्त प्रतिपादन है। यह अधिनियम एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है, जो भारतीय राजनीति, समाज और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका को न केवल स्वीकार करता है, बल्कि उसे संस्थागत आधार भी प्रदान करता है।

वास्तव में स्त्रियाँ समाज का दर्पण होती हैं। किसी भी समाज एवं राष्ट्र की स्थिति को वहाँ की नारियों की दशा देखकर आँका जा सकता है। राष्ट्र की स्त्रियाँ सशक्त होंगी, तो राष्ट्र भी सशक्त होगा। भारत की गौरवशाली हिंदू संस्कृति में नारी का स्थान हमेशा से श्रेष्ठ रहा है। भारत में महिलाओं की भूमिका प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रही है। नारी को हमेशा से 'शक्ति' और 'सृजन' का प्रतीक माना गया है। भारत में एक तरफ जहाँ गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने वेदों की ऋचाओं को गढ़कर ज्ञान परम्परा को समृद्ध किया है, तो वही दूसरी तरफ 'रानी लक्ष्मीबाई' और 'रानी दुर्गावती' जैसी वीरांगनाओं ने अपने शौर्य और पराक्रम से राष्ट्र निर्माण में अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित की है।

किन्तु आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लंबे समय तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत सीमित रहा है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' इसी ऐतिहासिक असंतुलन को सुधारने का प्रयास है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को विधायिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व (33 प्रतिशत) प्रदान करना है, जिससे वे न केवल राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनें बल्कि निर्णय-निर्माता भी बन सकें। यह अधिनियम इस भावना पर आधारित है कि जब नीतियां बनाने वाली मेज पर महिलाएँ होंगी, तो समाज की आधी आबादी की वास्तविक आवश्यकताओं का समुचित रेखांकन संभव हो सकेगा।

ये सच है कि युग परिवर्तन के साथ-साथ हमारे आचार-विचार में और हमारी आवश्यकताओं में परिवर्तन होना समीचीन है, परन्तु जीवन के मौलिक सिद्धांतों में विभेद होना कदापि ईष्ट नहीं है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि हमारी महान् संस्कृति में समय परिवर्तन के साथ-साथ स्त्रियों की दशा में भी परिवर्तन होते चले गए। नारी समानता का विचार हाशिए पर चला गया। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष ने स्वयंभू बनकर स्वयं को श्रेष्ठ और स्त्री को निम्नतर मान लिया। किन्तु वास्तव में नारी निम्नता का यह विचार भेदभाव मूलक और निंदनीय है। स्त्री किसी भी रूप में पुरुष से कमतर नहीं है।

चाणक्य कहते हैं-
स्त्री द्विगुण आहारो लज्जा चापि चतुर्गुणा।
साहसं षड्गुणं चैव कामश्चाष्टगुणः स्मृतः॥

अर्थात् पुरुषों की अपेक्षा स्त्री की बुद्धि चार गुना अधिक होती है, आहार दो गुना अधिक होता है और उनका साहस पुरुषों की तुलना में छः गुना अधिक होता है।

भारत की आधी आबादी के इसी साहस और क्षमता को राष्ट्र निर्माण के सरोकार में सहभागी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार स्त्री समुदाय के उत्थान, कल्?याण और सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना', 'सुकन्या समृद्धि योजना', 'प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना', 'तीन तलाक निषेध', 'आयुष्मान भारत' और जल जीवन मिशन जैसे अनेक कल्याणकारी कदम उठाए हैं।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महिलाओं के प्रति पवित्र चिंतन का एक और ऐतिहासिक कदम है। यह अधिनियम महिलाओं के अधिकारों, राष्ट्र निर्माण में उनकी सशक्त सहभागिता और उज्जवल एवं समावेशी भविष्य की आधारशिला है। इस अधिनियम के द्वारा विधायिका में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा। यह अधिनियम नारी को उसके वास्तविक स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक नैतिक और अनिवार्य संकल्प है।

इस अधिनियम के दूरगामी प्रभाव अनेक स्तरों पर दिखाई देंगे। महिलाएँ नीति-निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगी, समाज में लैंगिक समानता को प्रोत्साहन मिलेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा जैसे विषयों पर अधिक संवेदनशील नीतियाँ बनेंगी और भविष्य में महिलाओं के लिए प्रेरणा और अवसर दोनों बढ़ेंगे।

वास्तव में नारी सृष्टि की उत्पादिका और प्रतिपालिका है। मनुष्य के कंटकाकीर्ण मार्ग को सुगम बनाने का एकमात्र साधन स्त्री ही है। माँ दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में नारी सृजन, ज्ञान और समृद्धि की प्रतीक है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' इसी दार्शनिक सत्य को भारत की आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मूर्तरूप प्रदान करता है।

हमारी संस्कृति में कहा गया है- 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।' इसी पुण्य भाव को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के माध्यम से महिलाओं को उनके समुचित अधिकार और विधायिका में उनकी समुचित सहभागिता को सुनिश्चित कर चरितार्थ करने का पुनीत कार्य कर रहे है।

माधव मास और राधाचूड़ा

प्रकृति
डॉ. शोभा सिंह

माधव मास की तपस्विनी हिरण्यमयी धूप में सड़क के किनारे खड़े अमलतास को देखते ही राधिका की पीताम्बरी ओढ़नी याद आ गई। दूर से ही उसकी झिलमिलाती सुवर्णिम कोर आँखों को बाँध लेती थी। निकट पहुँचकर मनमोहिनी ताल पर शाखा-प्रशाखाओं से लटकते पीत-पुष्पों के रेशमी झूमर प्रेयस का नाम जपने लगते।

यह वही राधाचूड़ा वृक्ष है जिसे संस्कृत के कवियों ने कर्णिकार कहा, लोक ने अमलतास पुकारा और आयुर्वेद ने आरग्वध तथा व्याधिघात की उपाधि दी। वनस्पति-शास्त्र का रूखा नाम 'कैसिया फिस्टुला' उसके सौंदर्य को नहीं पहचान सका, पर देवभाषा के रसिकों ने इसे स्वर्णवृक्ष, नृपद्रुम और कृतमाल जैसे राजसी नामों से अलंकृत किया। वैशाख मास में यह सुकोमल कर्णाभूषण रूपसियों के कर्ण-कुहरों में प्रेम-रागिनियाँ गुनगुनाता है और राधा-कृष्ण के प्रेम-रस का जीवंत साक्षी बन जाता है। जब जेठ की प्रचंड निदाघ अन्य वृक्षों को क्रंदन करने पर मजबूर कर देती है, तब यह स्वर्ण-किरीटधारी तपस्वी धूनी रमाए स्मित-मुख झूमता है और नृपद्रुम नाम सार्थक करता है।

वर्णप्रकर्षे सति कर्णिकारं दुनोति निर्गन्धतया स्म चेतः।
प्रायेण सामर्ग्यविधौ गुणानां पराङ्मुखी विश्वसृजः॥'

सुभाषितकार की कहन है कि इतना सुंदर रूप होने पर भी निर्गंध होने से कर्णिकार मन को दुःखी करता है। सृष्टिकर्ता प्रायः गुणों की पूर्णता में उदासीन रहते हैं। माना कि इसके फूलों में सुगंध नहीं, पर सौंदर्य की वह दाहकता है दीप्ति है कि मन पिघल जाए। किंवदंती है कि नायिकाओं के निकट आते ही यह हर्ष से झूम उठता और दोहद से खिल जाता है। गंध-त्यागी यह कोमल पुष्प सिखाता है कि प्रेम में स्व की पहचान मिटाकर ही सच्चा मिलन घटित होता है। अपने कोमल स्वर्ण-पल्लवों से प्रेम का सहज और सुंदर व्याकरण रचता है अमलतास।

हिमालय की उपत्यका में इस स्वर्णिम वृक्ष की एक पावन कथा अंकित है। गिरिकन्या पार्वती ऋतुपुष्पों से अलंकृत होकर योग-समाधि से जागे शिव को प्रणाम करती हैं, तभी उनकी घननील अलकों से एक नवीन कर्णिकार-पुष्प शिव-चरणों में गिर ता है। कविकुलगुरु कालिदास लिखते हैं:

'उमाह्यपि नीलाह्यलकमध्यशोभि विस्त्रंसयन्ती नवकर्णिकारम्।
चकार कर्णच्युतपल्लवेन मूर्ध्ना प्रणामं वृषभध्वजाय॥ '
(कुमारसंभवम्)

यह दृश्य केवल श्रृंगार की सुंदरता नहीं, समर्पण की गहनता भी दिखाता है। अशोक के रक्तिम पुष्प न लजाए, मालती-माल न झुकी, बकुल-मधूक मौन रहे, पर कर्णिकार विनत होकर प्रेम की आर्त पुकार बन गया। कविकुलगुरु वसंत ऋतु में रूपसियों द्वारा कर्णिकार-पुष्पों से श्रृंगार का मनमोहक चित्रण करते हैं:

'अहितं तत्कुसुमं युवतयः अलके दधुः'
(ऋतुसंहार)

प्रेमी द्वारा लाए गए कोमल, स्वर्णिम, यज्ञ-ज्वाला जैसे तेजस्वी कर्णिकार के पुष्प युवतियाँ अपने अलकों में सजाती हैं। विक्रमोर्वशीय नाटक में राजा पुरूरवा के आगमन का वर्णन करते हुए कर्णिकार को दीपमाला से उपमा दी गई है। वाल्मीकि रामायण में पम्पासर के तट पर विरही श्रीराम जब 'पुष्पितां कर्णिकारस्य यष्टिम् परमशोभिताम्' देखते हैं, तो उनका हृदय जानकी की स्मृतियों में डूब जाता है।

राधाचूड़ा संयोग और वियोग दोनों का साक्षी है। एक ओर पार्वती के मस्तक से गिरकर उमा को महेश्वर से मिलाता है, दूसरी ओर पम्पासर पर रघुनाथ को जानकी-विरह में भिगोता है। ताप और दाहकता का, सौंदर्य और विनम्रता का, प्रतीक्षा और मिलन का अनुपम रूप है – कर्णिकार।

पर्यावरण
डॉ. अंशुल उपाध्याय
लेखक रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग दिल्ली की फार्मर सीनियर यूजीसी रिसर्च एसोसिएट हैं।

पश्चिम एशिया के पास है, मीठे जल के स्रोतों की भारी कमी

पश्चिम एशिया का तापमान मुख्य रूप से गर्म और शुष्क रहता है, जहाँ गर्मियाँ बहुत गर्म (40 डिग्री से अधिक) और सर्दियाँ हल्की से ठंडी होती हैं। यहाँ अरब प्रायद्वीप जैसे क्षेत्रों में भीषण गर्मी और रेगिस्तानी जलवायु है, जबकि भूमध्यसागरीय तटों पर मौसम अधिक मध्यम और नम रहता है। वर्षा बहुत कम होती है, जो मुख्य रूप से सर्दियों में होती है। जिनमें,लेबनान, इज़राइल गर्मियों में गर्म और सर्दियों में नरम/बारिश रहते हैं। ईरान, तुर्की में सर्दियाँ लंबी और बर्फीली होती है। जबकि अधिकांश क्षेत्रों में दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। यहां अधिकांश इलाकों में सर्दियां केवल दिसम्बर से फरवरी तक ही रहती है।

एशिया महाद्वीप को अगर देखा जाए तो पश्चिमी एशिया और मध्य एशियाई प्रदेशों में मीठे जल के श्रोतों की काफ़ी कमी है। क्योंकि, इन क्षेत्रों में अधिकांश रेगिस्तान है और यहां की जलवायु भी शुष्क है। बरसात न के बराबर होती है, और गर्मी चरम पर रहती हैं। और जो थोड़ी बहुत मीठे पानी की नदियां है उनका जल भी तेज धूप के कारण वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। इसलिए पश्चिमी एशिया के अधिकांश देश जो समुद के किनारे है समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाकर पीने के लिए आप मजबूर हैं। इन्हीं प्लांट को डिसेनिलेशन प्लांट कहते हैं। सऊदी अरब में इन प्लांटों की संख्या सर्वाधिक है।

पश्चिम एशिया का तापमान मुख्य रूप से गर्म और शुष्क रहता है, जहाँ गर्मियाँ बहुत गर्म (40°C से अधिक) और सर्दियाँ हल्की से ठंडी होती हैं। यहाँ अरब प्रायद्वीप जैसे क्षेत्रों में भीषण गर्मी और रेगिस्तानी जलवायु है, जबकि भूमध्यसागरीय तटों पर मौसम अधिक मध्यम और नम रहता है। वर्षा बहुत कम होती है, जो मुख्य रूप से सर्दियों में होती है। जिनमें, लेबनान, इज़राइल गर्मियों में गर्म और सर्दियों में नरम/बारिश रहते हैं। ईरान, तुर्की में सर्दियाँ लंबी और बर्फीली होती है। जबकि अधिकांश क्षेत्रों में दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। यहां अधिकांश इलाकों में सर्दियां केवल दिसम्बर से फरवरी तक ही रहती है।

वर्तमान समय में खाड़ी के डीसैलीनेशन संयंत्र के पास हमला किया गया था जो ईरान पर अमेरिका और इजरायल के 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों के बाद ये सबसे दुर्दशा पूर्ण कृत्य था। यह संघर्ष कई बार खाड़ी के महत्वपूर्ण जल और ऊर्जा ढांचे के करीब पहुंच चुका है। दो मार्च को दुबई के जेबेल अली बंदरगाह के पास ईरानी मिसाइलें व ड्रोन से हुए हमले दुनिया के सबसे बड़े डीसैलीनेशन संयंत्रों में से एक से लगभग 12 मील दूर ही गिरे थे। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह एफ-1 जल व बिजली परिसर और कुवैत के दोहा वेस्ट डीसैलीनेशन संयंत्र के आसपास भी नुकसान की खबरें आईं। बहरीन ने भी अपने एक जल संयंत्र को ड्रोन हमलों से नुकसान पहुंचने का आरोप लगाया है, जबकि ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमले में होर्मुज जलडमरूमध्य के पास केश्म द्वीप स्थित एक डीसैलीनेशन संयंत्र क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे 30 गांवों की जल आपूर्ति प्रभावित हुई।

जिस मानव समाज की सुख सुविधाओं और पूर्ति के लिए युद्ध किया जा रहा है यदि उसी मानव समाज की एक बड़ी आबादी को प्यास के कारण तड़प कर मरना पड़े तो फ़िर ऐसे युद्ध में जीत का क्या अर्थ होगा? जिस जनता पर शासन करने के लिए युद्ध हो रहा है जब वही जनता न रहेगी तो कितनी भी बड़ी जीत हो वो तो निरर्थक ही साबित होगी। एशिया के वो देश, जहां डिसेनिलेशन प्लांट लगाए गए है कुवैत,संयुक्त अरब अमीरात,बहरीन,लीबिया, यमन, और जॉर्डन ये सभी पश्चिम एशियाई देश है।

पश्चिम एशिया में संयुक्त अरब अमीरात में जल संरक्षण के कई उपायों पर काम किया जा रहा है, जिनमें अमीराती नागरिकों के लिए जल खपत संकेतक लागू करना ,जल शुल्क और सब्सिडी का पुनर्संतुलनकरना आदि शामिल हैं। अकेले अबू धाबी में 1,300 से अधिक भूजल निगरानी केंद्रों का निर्माण; और खारे भूजल से मीठा पानी बनाने में सक्षम सौर ऊर्जा संचालित विलवणीकरण संयंत्रों का विस्तार। भविष्य में किए जाने की संभावना है। वर्तमान में संघीय विद्युत और जल प्राधिकरण शैवाल का उपयोग करके पानी से नमक सोखने वाली एक नई तकनीक का परीक्षण कर रहे है। यदि यह तकनीक प्रभावी साबित होती है, तो संयुक्त अरब अमीरात इसे लागू करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। यह संयुक्त अरब अमीरात की इस बढ़ी हुई जागरूकता का प्रतीक है कि जल संकट की समस्याओं का पूरी तरह से समाधान करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के महत्वपूर्ण निवेश के साथ-साथ मौलिक सोच की आवश्यकता होती है।

सऊदी अरब, जो विश्व में खारे पानी के सबसे बड़े उत्पादक देश है, ने अपने विलवणीकरण संयंत्रों को चलाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों का उपयोग करके अधिक टिकाऊ जल आपूर्ति समाधान अपनाने के अपने हालिया प्रयासों में भी सक्रियता दिखाई है। इसका जल्द ही पूरा होने वाला 130 मिलियन डॉलर का अल खफजी संयंत्र विश्व का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र होगा, जो स्वच्छ फोटोवोल्टिक (पीवी) ऊर्जा का उपयोग करके प्रतिदिन 60,000 घन मीटर पानी का उत्पादन करेगा।

आने वाले दशक में न केवल पश्चिम एशिया बल्कि विश्व के अधिकांश भाग को मीठे जल की कमी से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में चल रहे युद्धों के निवारण के लिए ठोस कदम उठाने का प्रयास करना होंगा। और विश्व के समस्त देशों को जल संरक्षण में अधिकता और भूमिगत जल के दोहन में कमी लाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। तभी भविष्य की आने वाली पीढ़ियों में जल की आपूर्ति को बहाल किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित धार भ्रमण की तैयारियाँ तेज

प्रभारी कलेक्टर अभिषेक चौधरी ने जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली

धार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आगामी 19 अप्रैल को धार जिले के तहसील धरमपुरी अंतर्गत ग्राम सिरसोदिया में प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। इस संबंध में प्रभारी कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक चौधरी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

प्रभारी कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के भ्रमण के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए। कार्यक्रम स्थल, मंच, पाण्डाल और पार्किंग क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बेरिकेडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए गए हैं। साथ ही, हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक के रूट का गंभीरता से परीक्षण करने और निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए 24 घंटे जनरेटर बैकअप रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सिरसोदिया में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम के लिए अधिकारियों को विशिष्ट दायित्व सौंपे गए हैं। श्री चौधरी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक वेदी, हवन कुण्ड और पाण्डाल की साज-सज्जा मानक अनुरूप हो। विवाह जोड़ों के लिए आवश्यक सामग्री, पूजन व्यवस्था और प्रशाधन कक्ष (ड्रेसिंग रूम) की व्यवस्था समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्यक्रम स्थल पर आने वाले नागरिकों के लिए पेयजल, अस्थाई शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड पर एम्बुलेंस, चिकित्सक दल और जीवन रक्षक उपकरणों के साथ तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। श्री प्रमोद सिंह गुर्जर, एसडीएम मनावर को संपूर्ण कार्यक्रम व्यवस्था का प्रभारी बनाया गया है।

बैठक के अंत में प्रभारी कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सौंपे गए दायित्वों को समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस दौरान अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अथर्व बांगर ने 12वीं में फिर लहराया परचम, 94.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की

अथर्व ने 10वीं कक्षा में भी 96 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिले में टॉप किया था

धार। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (12वीं) वर्ष 2026 के घोषित परिणामों में अथर्व बांगर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 94.2 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में सफलता हासिल की है। उनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से परिवार, विद्यालय और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अथर्व बांगर, धार शहर में स्थित टेलेंट पब्लिक स्कुल के मेधावी छात्र हैं। विद्यालय के संचालक गजेंद्र शर्मा ने अथर्व की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसे विद्यालय के लिए गर्व का क्षण बताया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

अथर्व ने 12वीं में सभी विषयों में डिस्टिंक्शन प्राप्त की है। अंग्रेजी और बायोलॉजी में 98-98 अंक हासिल कर उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, वहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में 93-93 अंक तथा हिंदी में 89 अंक प्राप्त किए। कुल 500 में से 471 अंक प्राप्त कर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया।

गौरतलब है कि अथर्व ने 10वीं कक्षा में भी 96 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिले में टॉप किया था। लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उन्होंने एक बार फिर अपनी मेहनत और लगन का परिचय दिया है।

अथर्व ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन के मार्गदर्शन को दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर परिजनों, शिक्षकों और मित्रों ने उन्हें बधाई दी है।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस महाराजा भोज शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय धार के 3 विद्यार्थियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन

माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 में टिशा ठाकुर, तमन्ना चौहान, यश रावत का राष्ट्रीय स्तर पर चयन

धार। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धार के विद्यार्थियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 का आयोजन तीन चरणों में किया गया था। जिसमें देश के 12 लाख प्रतियोगियों में से मध्य प्रदेश से कुल 990 युवाओं का चयन किया गया। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में टिशा पिता बहादुर सिंह ठाकुर (बी.ए. प्रथम वर्ष), तमन्ना पिता सुभाष चौहान (बी.ए. प्रथम वर्ष) एवं यश पिता संतोष रावत (बीएससी. प्रथम वर्ष) का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। सभी को प्रमाण पत्र प्रदान किये गये।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस धार के प्राचार्य डॉ. एस.एस. बघेल प्रशासनिक अधिकारी डॉ. आयशा खान, डॉ प्रभा सोनी, रासेयो जिला संगठक डॉ. के. एस. चौहान, रासेयो कार्यक्रम अधिकारी डॉ. लक्ष्मी बघेल, डॉ अभय वर्मा एवं महाविद्यालय परिवार द्वारा प्रतिभागियों के उज्वल भविष्य की कामना कर शुभकामनाएं प्रेषित की गई।

सरकारी जमीनों पर चल रही शराब की दुकानें

नए ठेकों के बावजूद पुरानी अतिक्रमण की हुई जगहों पर संचालित हो रही दुकानें

बैतूल। आबकारी विभाग ने शराब दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया तो लगभग पूरी कर ली है, लेकिन इन दुकानों के संचालन की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। यही वजह है कि ठेके के बाद ये शराब दुकानें सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण कर चलाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। यहां वर्षो से सरकारी जमीनों पर शराब दुकान संचालित हो रही है, लेकिन इसकी तरफ प्रशासनिक जिम्मेदारों ने अब तक कोई ध्यान ही नहीं दिया। नतीजतन शराब ठेका लेने वाले

अपनी मनमर्जी से शराब दुकानें संचालित कर रहे हैं। इससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है। जिम्मेदार अधिकारियों के पास इस संबंध में शिकायतें पहुंचाने के बावजूद बात आई-गई हो जाती है। ठेकेदार मजे से सरकारी जमीनों पर दुकानें संचालित कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बैतूल जिले की शराब दुकानें करीब 3 सौ करोड़ रुपए से ठेके पर ली जाती है। जिले में कुल 61 दुकानों की नीलामी होनी थी, जिसमें से 57 दुकान का ठेका दिया जा चुका है। अभी चार दुकान बची हुई है जिसमें बैतूल गंज-1, आमला-1, बगडोना एवं सारणी की दुकान का ठेका अभी तक नहीं हो पाया है। इधर बैतूल में शराब दुकानों के निष्पादन में लापरवाही पर आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने जिला आबकारी अधिकारी अंशुमन चिढ़ार को निलंबित कर दिया था। यह कार्रवाई वर्ष 2026-27 के लिए शराब दुकानों की टेंडर प्रक्रिया में अपेक्षित परिणाम न मिलने और शासन के राजस्व हित प्रभावित होने के कारण की गई है।

इन सरकारी जमीनों पर संचालित हो रही दुकान–

बैतूल शहर के सदर ओवर ब्रिज के नीचे रेलवे लाइन के किनारे की सरकारी जमीन पर शराब दुकान संचालित होते हुए देखी जा सकती है। जानकारी के अनुसार अन्य स्थानों पर भी सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से शराब दुकान संचालित की जा रही है। प्रशासनिक जिम्मेदारों के माध्यम से भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके कारण सरकारी जमीनों पर शराब दुकानें धड़ल्ले से चल रही है। सवाल उठता है कि आबकारी विभाग ठेकेदारों को सिर्फ शराब बेचने का लाइसेंस देती है, न की सरकारी जगह पर दुकान चलाने का, लेकिन लगता तो यह है कि ठेकेदार इसे जमीन का लाइसेंस समझ बैठते हैं। इससे वे अवैध रूप से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान संचालित करते रहते हैं, नियमानुसार ठेकेदारों को खुद ही अपनी शराब दुकान का इंतजाम करना चाहिए, लेकिन शासकीय काम के ठेके की आड़ में एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए कहीं भी सरकारी जमीनों पर दुकान खड़ी कर दी जाती है। अब ठेके बदल रहे हैं, लेकिन शराब दुकान उन्हीं सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर चलाई जा रही है।

आहतें भी सरकारी जमीन पर हो रहे संचालित

बैतूल जिले में केवल शराब दुकानें ही सरकारी जमीन पर संचालित नहीं हो रही है बल्कि पूरे प्रदेश में बंद हो चुके आहते भी इन शराब दुकानों के आस-पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। कोठीबाजार के बस स्टैंड पर भी गुपचुप तरीके से रेस्टोरेंट के नाम पर आहता चलाया जा रहा है। आबकारी अमला व पुलिस इसकी पड़ताल करें, तो सफलता जरूर मिलेगी।

इनका कहना–

बैतूल शहर के सदर क्षेत्र में ओवर ब्रिज के नीचे, रेलवे लाइन के किनारे की सरकारी जमीन, जिस पर शराब दुकान संचालित हो रही है, वह है तो नजूल की, परंतु नजूल की जमीन पर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई तहसीलदार के माध्यम से की जाती है, वे ही अतिक्रमण हटाएंगे। इस संबंध में आप उनसे संपर्क कर लीजिए।

– मकसूद अख्तर, संयुक्त कलेक्टर एवं नजूल अधिकारी, बैतूल

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला नजूल विभाग देखता है और रही बात अवैध अहाता चलाए जाने की, तो पूरे प्रदेश में अहाता चलाए जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यदि इसके बावजूद अहाता चलाया जा रहा है, तो आप इसकी लिखित शिकायत कीजिए, मैं जांच करवाकर कार्रवाई करवाऊंगी।

– लीला सिंग मुकाती,
प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी, बैतूल

सेकेंड ऑफिसर पद पर पदोन्नत हुए ओम द्विवेदी

बैतूल। नर्मदापुरम स्थित 13 मप्र बटालियन एनसीसी में आयोजित गरिमापूर्ण रैंक सेरेमनी में उत्कृष्ट विद्यालय बैतूल के एनसीसी अधिकारी ओम द्विवेदी को सेकेंड ऑफिसर के पद पर पदोन्नत किया गया। समारोह के दौरान कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एस पी सिंह एवं एडम ऑफिसर ले. कर्नल विवेक चुंदावत ने उनके कंधों पर सितारे लगाकर इसे औपचारिक रूप प्रदान किया। द्विवेदी को यह उपलब्धि डीजी एनसीसी नई दिल्ली व कार्यालय बटालियन से सौंपे गए दायित्वों के समयाविधि व ज़ीरो एरर कार्यशैली के लिए मिली। भारतीय सेना से जुड़े लोग कहते है कि काम इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, इसी बात को एनसीसी अधिकारी ओम द्विवेदी ने अपने निरंतर परिश्रम, सेनानुरूप कार्य और समर्पण से सही साबित किया। लगभग 2 वर्ष के अल्पकाल में ही एनसीसी के साप्ताहिक प्रशिक्षणो के उत्कृष्ट संचालन, वार्षिक शिविरों में कैडेट्स का अनुशासित एवं शानदार प्रदर्शन और संबंधित गतिविधियों में नवाचार इस पदोन्नति का आधार बना। एनसीसी से जूड़ी सामुदायिक गतिविधियों में आधुनिक व रचनात्मक प्रयोगों ने भी उन्हें विशेष पहचान दिलाई, जिसकी प्रशंसा कमान अधिकारी द्वारा पूर्व में भी की जा चुकी है।

बीसीघाट में बच्चों को आंगनवाड़ी भेजने से पालकों का इनकार

बैतूल। आमला क्षेत्र के ग्राम बीसीघाट में आंगनबाड़ी सहायिका की दोबारा नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्राम पंचायत कोठिया के ग्रामीणों ने परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास आमला को ज्ञापन सौंपकर सहायिका कृष्णी यादव की नियुक्ति रद्द करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त सहायिका को पहले गंभीर लापरवाही और अनियमितताओं के चलते पद से हटा दिया गया था। उस समय बच्चों को आंगनवाड़ी में कुत्ते का जूठा पानी पिलाने जैसे गंभीर आरोप सामने आए थे, जिसकी पुष्टि के बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया था। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने अपने बच्चों को आंगनवाड़ी भेजना भी बंद कर दिया था अब ग्रामीणों का आरोप है कि 14 मार्च 2026 से उसी सहायिका कृष्णी यादव को पुनः आंगनबाड़ी केंद्र बीसीघाट में नियुक्त कर दिया गया है। इससे गांव में एक बार फिर रोष की स्थिति बन गई है। पालकों ने दो टूक कहा है कि जब तक उक्त सहायिका को हटाया नहीं जाता, वे अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र नहीं भेजेंगे।

नौ का दूल्हा और आठ साल की दुल्हन

वीडियो सामने आने के बाद पंडित जी से लेकर घोड़ी वाले तक फंसे, सब पर केस दर्ज

राजगढ़ (नप्र)। मध्य प्रदेश की राजगढ़ पुलिस ने 9 साल बालक और 8 बालिका का विवाह संपन्न करने पर माता-पिता सहित टेंट संचालक, घोड़ी संचालक, प्रिंटिंग प्रेस संचालक, हलवाई एवं पंडित के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग दूल्हे की हल्दी, मेहंदी और बारात की रस्मों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई और और राजगढ़ जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र के कुशालपुरा गांव पहुंचकर कार्रवाई की।

प्रशासन के दावे हुए फेल– महिला एवं बाल विकास विभाग और प्रशासन के द्वारा बाल विवाह की रोकथाम को लेकर लगातार अभियान चलाकर इसकी रोकथाम की बात कही जा रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए नाबालिग दूल्हा-दुल्हन के बाल विवाह का वीडियो ने प्रशासन के अभियान की पोल खोल दी है।

करनवास से भी सामने आया मामला– करनवास थाना क्षेत्र में भी एक नववर्ष की बच्ची की सगाई कर उसकी शादी 26 अप्रैल को तय कर दी गई थी। परिजनों की सहमति के ही रिश्तेदारों ने यह विवाह कर दिया। अब विवाह नहीं करने पर झगड़े में 9 लाख रुपए की मांग भी की जा रही है। इसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस और महिला बाल विकास से की है। अजय यादव, थाना प्रभारी भोजपुर ने बताया कि नाबालिग बालक एवं नाबालिग बालिका का विवाह दिनांक 14/04/2026 को संपन्न कराया गया था। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग, आहिंसा वेलफेयर सोसायटी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं ग्राम चौकीदार द्वारा बाल विवाह की पुष्टि की गई।

माता-पिता सहित अन्य लोगों पर दर्ज हुआ मामला– भोजपुर थाना प्रभारी अजय यादव ने बताया कि पुलिस ने पंचनामा तैयार कर मामले की गंभीरता को देखते हुए बालक एवं बालिका के माता-पिता सहित अन्य सहयोगी व्यक्तियों के साथ टेंट संचालक, घोड़ी संचालक, प्रिंटिंग प्रेस संचालक, हलवाई एवं पंडित के विरुद्ध थाना भोजपुर में अपराध क्रमांक 120/2026 अंतर्गत धारा 10 एवं 11, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई है।

पुलिस की अपील– जिला पुलिस एवं प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में सहयोग करें तथा ऐसी किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस या संबंधित विभाग को दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सारंग की नई पहल

समर कैंप आरोह-2026 नए स्वरूप में होंगे : मंत्री सारंग

भोपाल । खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने नई पहल शुरू करते हुए समर कैंप 'आरोह-2026' को नए स्वरूप में करवाने का निर्णय लिया है। इस बार व्यक्तित्व विकास एवं रचनात्मक गतिविधियों को भी समर कैंप में शामिल किया जा रहा है। इस संबंध में गुरूवार को तात्या टोपे खेल स्टेडियम में आयोजित प्रदेश के सभी खेल अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री श्री सारंग ने समर कैंप में नई गतिविधियों के बारे में बताया।

एक मई से शुरू होगा समर कैंप– मंत्री श्री सारंग ने कहा कि भोपाल सहित सभी जगह 1 मई से समर कैंप शुरू होगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट और क्यूआर कोड को स्केन करके इसमें 18 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। उन्होंने सभी खेल अधिकारियों से कहा कि इसमें युवा समन्वयकों से जुड़ कर इसका आयोजन/गतिविधियां ब्लॉक एवं ग्रामीण स्तर तक की जाए।

समर कैंप से सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण हो– मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक खेल विभाग के इस समर कैंप 'आरोह-26' की जानकारी हो और लोग इसमें शामिल हो। यह समर कैंप एक मूवमेंट के रूप में जाना जाए, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छता अभियान आदि। इसी प्रकार यह समर कैंप केवल गतिविधि केन्द्रित नहीं होकर बच्चों और परिवार सहित समाज को जोड़ने का एक सकारात्मक संदेश दें। हमारा उद्देश्य केवल प्रतिभा का विकास ही नहीं बल्कि एक ऐसे सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण भी है जो परिवार का गौरव एवं राष्ट्र और समाज का आधार बने।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि खेल अधोसंरचना का विकास, प्रतिभाओं को निखारें वाले कोच और प्रतिभाएं तलाशना हमारा मुख्य उद्देश्य है। साथ ही खिलाड़ी को उत्तम खिलाड़ी बनाना और युवाओं को खिलाड़ी बनाने में कोचेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। युवाओं का शारीरिक और मानसिक समग्र विकास खेल के जरिये ही हो सकता है। विभाग का मुख्य काम भी युवाओं को खेल से जोड़ना और युवाओं का कल्याण करना है, जो मानसिक एवं बौद्धिक विकास के जरिये किया जा सकता है। इसके लिए जागरूकता एवं काउंसिंग जैसे कार्यक्रम को भी शामिल किया जा सकता है। बैठक में खेल संचालक श्री अंशुमान यादव एवं संयुक्त संचालक श्री बी.एस. यादव सहित प्रदेश के खेल अधिकारी मौजूद थे।

जनगणना ड्यूटी से बचने जिलों में बीस हजार आवेदन

गुना कलेक्टर का नया फार्मूला, बेहतर प्रदर्शन करने वाले 6 कर्मचारियों को देंगे 10-10 हजार

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जनगणना के काम में लगाए जाने वाले कर्मचारियों ने ड्यूटी कैंसिल कराने के लिए जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया है। बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा में ड्यूटी कैंसिल कराने के लिए अलग-अलग दस हजार से अधिक आवेदन कलेक्टरों, निगम आयुक्तों और सीनियर अफसरों के माध्यम से आ चुके हैं।

छोटे जिलों में भी दस हजार से अधिक आवेदन ड्यूटी कैंसिल कराने के लिए पहुंचे हैं। उधर गुना कलेक्टर किशोर कान्याल ने खुद को मिलने वाला 60 हजार रुपए का मानदेय छह श्रेष्ठ कर्मचारियों को नकद पुरस्कार के रूप में देने का ऐलान कर दिया है। ड्यूटी से मुक्ति के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों द्वारा वैवाहिक कार्यक्रमों, स्वास्थ्य खराब होना और एलर्जी समेत कई अन्य कारण बताए गए हैं। जिन जिलों में नगर निगम है वहां के नगर निगम आयुक्तों को शहरी क्षेत्र की जनगणना की जिम्मेदारी सौंपी गई है और प्रदेश के 16 नगर निगमों में करीब 14 हजार आवेदन जनगणना ड्यूटी कटवाने के लिए मिले हैं। कलेक्टरों का कहना है कि कई मामलों में वास्तविक स्थिति को देखते हुए जनगणना न करने के आवेदन पर रिलीफ भी दी जा रही है, लेकिन जिनके मामले में बहाने साफ नजर आते हैं, उन्हें इससे राहत नहीं दी जा रही है क्योंकि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का काम है। जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि सरकार इसके बदले उन्हें कम से कम 25 हजार रुपए मानदेय पूरी जनगणना पर देगी।

गुना कलेक्टर 10-10 हजार छह कर्मचारियों को नकद देंगे– उधर गुना कलेक्टर किशोर कान्याल ने जनगणना में फास्ट वर्किंग के लिए जनगणना में तैनात कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि वे कलेक्टर के रूप में उन्हें मिलने वाला मानदेय शिक्षकों को पुरस्कार के रूप में बांटेंगे।

संक्षिप्त समाचार

लिखड़ी उपकेंद्र में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर से 575 किसानों को मिलेगा बेहतर बिजली सपोर्ट

बैतूल ,(निप्र)। विद्युत वितरण कंपनी के उत्तर संभाग के अंतर्गत वितरण केंद्र आमला ग्रामीण के ग्राम लिखड़ी स्थित 33/11 केवी उपकेंद्र में मंगलवार को 3.15 एमवीए क्षमता का अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। इस नए ट्रांसफार्मर के लगने से क्षेत्र में लंबे समय से बनी वोल्टेज समस्या का समाधान होगा। साथ ही लगभग 575 किसानों को सिंचाई के लिए गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे कृषि कार्यों में सुगमता आएगी। इस अवसर पर उप-महाप्रबंधक निर्माण संभाग श्री दीपक भूसारे, सहायक प्रबंधक एसटीएम श्री दिनेश्वर बांसोड़ सहित विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

रेत उत्खनन और तेज बहाव से खोखले हो रहे तट:नर्मदा-तवा संगम पर 10 मीटर तक बढ़ा कटाव

नर्मदापुरम,(निप्र)। नर्मदापुरम में नर्मदा और तवा नदी के किनारों पर कटाव रोकने के लिए अब तक कोई ठोस काम नहीं हो सका है। संगम तट बांद्राभान में कटाव 10 मीटर तक बढ़ गया है, जिससे बांद्राभान सड़क और पास स्थित स्कूल पर खतरा मंडरा रहा है। रेत के अनियंत्रित उत्खनन और बारिश में धाराओं के टकराव से पैदा होने वाले भंवर तटों को नीचे से खोखला कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, गंगा और ब्रह्मपुत्र की तर्ज पर यहाँ 'स्पर तकनीक' का उपयोग कर धारा को बीच की ओर मोड़ना जरूरी है। जल संसाधन विभाग ने बांद्राभान और ब्रिज के पास कटाव रोकने के लिए 15-15 करोड़ के दो प्रस्ताव शासन को भेजे हैं। फिलहाल मंगलवारा और विवेकानंद घाट पर पिचिंग का कार्य जारी है, लेकिन बांद्राभान में स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। तटों के कटाव के दो मुख्य कारण हैं। पहला, बारिश में तवा का तेज बहाव नर्मदा से टकराकर भंवर पैदा करता है, जो ड्रिल मशीन की तरह किनारों को काटते हैं। दूसरा, मशीनों से रेत निकालने के कारण नदी का तल उबड़-खाबड़ हो गया है, जिससे तटों का कुशन जैसा प्राकृतिक सपोर्ट खत्म हो गया है।

नरखेड़ा जागीर का 1.972 हेक्टेयर तालाब हुआ अतिक्रमण मुक्त

विदिशा ,(निप्र)। सिरोंज अनुविभाग में जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। एसडीएम सिरोंज श्री हरिशंकर विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम नरखेड़ा जागीर स्थित तालाब, जो सर्वे नंबर 168 रखवा अंतर्गत 1.972 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, लंबे समय से अतिक्रमण की चपेट में था। प्रशासन द्वारा 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के तहत सुनियोजित कार्रवाई करते हुए इस तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इस कार्यवाही से न केवल जल स्रोत का संरक्षण सुनिश्चित हुआ है, बल्कि क्षेत्र में जल स्तर सुधारने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दिशा में भी सकारात्मक कदम उठाया गया है। एसडीएम श्री विश्वकर्मा ने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी, ताकि सभी पारंपरिक जल स्रोतों को संरक्षित कर आमजन को इसका लाभ मिल सके।

खेत पर पानी देने गए मजदूर की संदिग्ध मौत:हरदा में 1 घंटे बाद गेट पर मिला शव

हरदा,(निप्र)। हरदा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रन्हाईकला में बीती मंगलवार रात खेत पर पानी देने गए एक मजदूर विश्राम गठिया का शव 1 घंटे बाद संदिग्ध परिस्थितियों में खेत के गेट पर मिला है। मृतक के सिर और मुंह पर चोट के निशान मिले हैं, जिसे लेकर उसके बेटे ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने एक्सीडेंट की सूचना पर मर्ग कायम कर बुधवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की जांच कर रही है। ग्राम रन्हाईकला निवासी मजदूर विश्राम गठिया मंगलवार रात करीब 10 बजे किसान मुकेश दोगने के खेत पर पानी देने गया था। लगभग एक घंटे बाद, रात करीब 11 बजे उसका शव किसान के खेत के गेट के पास पड़ा मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मृतक के बड़े बेटे कन्हैया को दी। मौके पर पहुंचने पर कन्हैया ने देखा कि उसके पिता के सिर और मुंह पर चोट के निशान थे और खून बह रहा था। इसके बाद उसने तत्काल परिजनों और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। मृतक के बेटे ने अपने पिता की हत्या की आशंका जताई है। बताया गया है कि मृतक विश्राम घर में अकेला कमाने वाला था।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती पर विदिशा में गरिमामय आयोजन, जनप्रतिनिधियों ने विचारों को अपनाने का किया आह्वान

समरसता भोज में सभी ने एक साथ बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण की

विदिशा ,(निप्र)। भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर विदिशा जिले भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। प्रातः प्रभात फेरियों, माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, जिसमें नागरिकों एवं विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

विदिशा जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा डॉ भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर के विचारों को अपने जीवन में उतारकर ही हम उनके सच्चे अनुयायी बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने और उनके जीवन में आशातीत परिवर्तन लाने के सफल प्रयास किए जा रहे हैं।

विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन ने कहा कि बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान ने देश की अनेक कमियों को दूर कर सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बाबा साहब की जयंती को शासकीय स्वरूप दिया गया है तथा उनके जीवन से जुड़े स्थानों को तीर्थ-दर्शन के रूप में विकसित किया जा रहा है।

विधायक श्री टंडन ने कहा कि भारत रत्न डॉ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मंशा के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा गरीबो, शोषित और पिछड़े समुदाय को विकसित करने के लिए विशेष पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम सबको संविधान का पालन कर जागरूक नागरिक होने का परिचय देना चाहिए।

कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा ने भी संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि विपरित परिस्थितियों के बावजूद दृढ़ संकल्प और लक्ष्य के प्रति अडिग रहकर उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, जो हम सभी के लिए अनुकरणीय है।

रविन्द्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक भवन ऑडिटोरियम, विदिशा में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप अतिथियों द्वारा हितलाभ का वितरण भी किया गया। खासकर सफाई कामगारो का सम्मान शाल उडाकर व माला पहनाकर किया गया है। इससे पहले कार्यक्रम में संगोष्ठी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं जागरूकता गतिविधियां आयोजित कर समाज में समानता, शिक्षा एवं सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया।

जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के उपरांत समरसता भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उपरोक्त सहभोज कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी, विधायक श्री मुकेश टण्डन, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा, कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता, अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर, जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोड़िया, एसडीएम श्री क्षितिज शर्मा के अलावा विभिन्न विभागो के अधिकारी, कर्मचारियों ने सभी वर्गो के नागरिकों के साथ बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण की है।

उक्त कार्यक्रम में कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता,अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर, जिला पंचायत सीईओ श्री ओपी सनोडिया समेत विभिन्न विभागों के अधिकारीगण कर्मचारियों के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, स्कूली बच्चे, मौजूद रहे। आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ दीप्ति शुक्ला के द्वारा किया गया।

अम्बेडकर जयंती पर श्रमदान कर दिया जल संरक्षण का संदेश, जल चौपाल के माध्यम से जागरूकता

बैतूल ,(निप्र)। डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती जी के अवसर पर मध्यप्रदेश जन अभियान परिषदजिला बैतूल द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत 'जल स्त्रोत सेवा समागम 'द्वितीय चरण में ग्राम सेहरा स्थित प्राचीन तपतझिरा बावली पर श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला समन्वयक प्रिया चौधरी की उपस्थिति में हुआ।

इस अवसर पर प्राचीन बावली स्थल पर देव पूजन एवं वृक्ष पूजन कर स्थानीय ग्रामीणों एवं प्रस्फुटन समिति सदस्यों ने जल स्रोतों के संरक्षण का संकल्प लिया। इसके पश्चात सभी उपस्थित नागरिकों ने सामूहिक श्रमदान करते हुए बावली की साफ-सफाई एवं संरक्षण कार्य किया। कार्यक्रम में जय गुरुदेव उत्थान नवांकुर संस्था सहित ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति अमदर, नयागांव, सेहरा एवं अन्य ग्रामों के सदस्य सक्रिय रूप से शामिल हुए। स्थानीय ग्रामीणों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया।

तपतझिरा स्थल ग्राम सेहरा की एक महत्वपूर्ण जल धरोहर है, जो सामाजिक एकता एवं पर्यावरण जागरूकता का केंद्र भी है। यह एक प्राकृतिक जल स्रोत (झिरा/झरना) है, जहां वर्षभर जल का सतत रिसाव होता रहता है। यहां स्थित प्राचीन बावली/कुंड का उपयोग पूर्व में पेयजल एवं दैनिक आवश्यकताओं के लिए किया जाता रहा है और यह भूजल स्तर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कार्यक्रम के दौरान जल चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया तथा परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। आयोजन के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।

बाइक ट्रॉली से टकराई,बाजार से लौट रहे मां-बेटे की मौत:हरदा में भांजे को भी चोट

19 अप्रैल को शादी थी, खरीदारी करने गए थे

हरदा,(निप्र)। हरदा जिले के हंडिया थाना क्षेत्र में ग्राम मांगरूल नाके के पास मंगलवार रात शादी की खरीदारी कर लौट रहे बाइक सवार मां-बेटे की ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर में मौत हो गई। हादसे में उनके साथ मौजूद 12 वर्षीय भांजा गंभीर रूप से घायल हो गया।

मृतकों की पहचान ग्राम ऊंचांन निवासी अभिषेक कीर (21) और उनकी मां नर्मदी बाई (45) के रूप में हुई। अभिषेक की 19 अप्रैल को बारात जानी थी।

पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवा दिया। घायल भांजे को भोपाल रेफर करने की सलाह दी गई।

पाइप खाली कर लौट रहे ट्रैक्टर से टक्कर : जानकारी के अनुसार, ग्राम ऊंचांन निवासी अभिषेक अपनी मां नर्मदी बाई और 12 वर्षीय भांजे शुभम कीर के साथ शादी की खरीदारी करने हरदा गए थे। मंगलवार रात सवा आठ बजे तीनों बाइक से गांव लौट रहे थे।

ग्राम मांगरूल नाके पर वन विभाग चौकी के पास पाइप खाली कर हंडिया जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक टकरा गई। टक्कर में नर्मदी बाई और अभिषेक के सिर में गंभीर चोटें आई और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। भांजे शुभम की नाक में गंभीर चोट आई।

17 अप्रैल को माता पूजन का कार्यक्रम था

हादसे के बाद तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंडिया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मां-बेटे को मृत घोषित कर दिया। बड़े भाई भगवानसिंह कीर ने बताया कि अभिषेक की 19 अप्रैल को ग्राम गडरापुर में बारात जानी थी।

17 अप्रैल को माता पूजन और 18 अप्रैल को मंडप का कार्यक्रम था। अभिषेक दो भाइयों में छोटा था और उसकी तीन बहनें हैं। उसके पिता कुछ सालों से मानसिक रूप से बीमार हैं। उन्हें सुनाई भी नहीं देता।

मॉर्चुरी में रखे गए शव, आज होगा पोस्टमॉर्टम : पुलिस ने इस संबंध में मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे में घायल भांजे शुभम को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे भोपाल रेफर करने की सलाह दी गई है। दोनों शवों को जिला अस्पताल की मर्चुरी में रखा गया है और बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।

पैक्स सदस्यता महाअभियान का शुभारंभ, किसानों को सदस्यता व केसीसी वितरण के साथ दी गई वित्तीय साक्षरता की जानकारी

बैतूल ,(निप्र)। मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत सहकारिता विभाग एवं अपेक्स बैंक के निर्देशन में 14 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक नवीन सदस्यता महाअभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सेहरा में सदस्यता महाअभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम में सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या, बैतूल द्वारा हितग्राहियों को पैक्स सदस्यता के लिए आवेदन भरवाए गए तथा पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का वितरण किया गया। इस अवसर पर अपेक्स बैंक भोपाल से श्री राजकुमार गंगेले, उपायुक्त सहकारिता श्री के.के. शिव , बैंक की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री परिधि अग्रवाल, बैंक अधीक्षक सुश्री नीता निगम सहित बैंक के कर्मचारीगण, संस्थाओं के प्रशासक एवं बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान किसानों को वित्तीय साक्षरता के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। अधिकारियों ने किसानों को बैंकिंग सेवाओं का उपयोग, डिजिटल भुगतान, बचत की आदत, ऋण प्रबंधन तथा समय पर ऋण चुकौती के महत्व के बारे में जागरूक किया। साथ ही बताया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वे सरल एवं सस्ती दरों पर कृषि ऋण प्राप्त कर अपनी कृषि गतिविधियों को सशक्त बना सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि यह महाअभियान जिले की सभी कृषि साख सहकारी समितियों में संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को समिति का सदस्य बनाकर उन्हें सहकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें संगठित सहकारिता तंत्र से जोड़ना है।

फेस रिकग्निशन के माध्यम से राशन वितरण दिसम्बर 2026 तक होगा

रायसेन,(निप्र)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि पात्र परिवारों को उचित मूल्य दुकानों से फेस रिकग्निशन के माध्यम से राशन वितरण की योजना है। इसे दिसम्बर, 2026 तक प्रदेश में लागू किया जाएगा। मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि माह मार्च, 2026 में 1 करोड़ 24 लाख 34 हजार परिवारों को 2 लाख 72 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। शेष रहे परिवारों को 15 अप्रैल तक राशन का वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन का वितरण नियमित रूप से किया जा रहा है।

परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर जाकर पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन कर राशन वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

वृद्ध/दिव्यांगजन के बायोमेट्रिक सत्यापन विफल होने पर ऐसे हितग्राहियों को उनके आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर ओटीपी भेजकर राशन का वितरण किया जाता है। शारीरिक रूप से अक्षम हितग्राही जो उचित मूल्य दुकान पर जाकर राशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे लगभग 44 हजार 671 परिवार नामिनी के माध्यम से राशन लेने के लिये नामित किये गये हैं।

पात्र परिवार द्वारा वन नेशन वन राशनकार्ड के तहत देश/प्रदेश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त किया जा सकता है। मध्यप्रदेश के 36 हजार 486 परिवारों द्वारा अन्य राज्यों में तथा अन्य राज्यों के 7,252 परिवारों द्वारा मध्यप्रदेश में प्रति माह राशन प्राप्त किया गया है।

सतपाड़ा हाट गांव में अज्ञात बालिका की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई

विदिशा ,(निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता को आज सतपाड़ा हाट तहसील नटेरन जिला विदिशा में एक अज्ञात बालिका की सूचना प्राप्त हुई थी। कलेक्टर द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता कांसवा को उक्त अज्ञात बालिका को अपने संरक्षण में रखे जाने एवं माता पिता के बारे में पता लगाने संबंधी निर्देशित किया गया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संरक्षण अधिकारी श्री अनुज जैन एवं श्रीमती सरिता शुक्ला का दल बनाकर मौके पर भेजा गया। दल द्वारा मौके स्थल पर पहुंचकर सतपाड़ा हाट पुलिस चौकी से बालिका को अपने संरक्षण में लिया एवं बाल कल्याण समिति विदिशा के सामने प्रस्तुत किया गया।

बाल कल्याण समिति जिला विदिशा से अध्यक्ष राम बाबू प्रजापति, सदस्य चंद्रभान बघेल, सदस्य दिवान सिंह मीणा एवं श्रीमती लक्ष्मी शर्मा द्वारा संयुक्त आदेश से बालिका को शिशु गृह में रखने का आदेश किया गया है।

20 दिन बाद भी नहीं उठा 115 मीट्रिक टन गेहूं

नागरिक आपूर्ति निगम के स्टॉफ पर लगाए रुपए मांगने के आरोप, पहले भी की शिकायत

नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक के आदेश के बावजूद श्रीनाथ वेयरहाउस से 20 दिन बाद भी गेहूं का उठाव नहीं किया गया। जबकि नियमों के अनुसार माल 5 दिन के भीतर उठाया जाना चाहिए था। देरी के कारण वेयरहाउस संचालक परेशान हैं।

वेयरहाउस संचालक के प्रतिनिधि 73 वर्षीय मोहन पालीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निगम की एक कनिष्ठ अधिकारी ऋतु कुमरे, प्रदाय केंद्र प्रभारी पिपरिया आयुष अवधिया और भरत कुमार(सर्वेयर) द्वारा गेहूं उठाने के लिए 20 रुपए प्रति क्विंटल की रिश्वत मांगी गई। राशि नहीं देने पर 20 दिन बाद भी 115 मीट्रिक टन गेहूं का उठाव नहीं किया गया।

2023-24 का गेहूं अब तक पड़ा, 23 मार्च को हुआ था आदेश

मोहन पालीवाल ने बताया कि उनकी पत्नी शोभा पालीवाल श्रीनाथ वेयरहाउस की संचालिका हैं और वे स्वयं प्रतिनिधि के तौर पर देखरेख करते हैं। वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया करीब 115 मीट्रिक टन गेहूं शोभापुर स्थित वेयरहाउस में रखा है। इसके उठाव के आदेश 23 मार्च 2026 को दिए गए थे, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई।

पालीवाल ने बताया कि वर्ष 2021-22 में भी उनके वेयरहाउस में रखा 169.77 क्विंटल गेहूं खराब हो गया था। इसे डीसीसी घोषित कर दिया गया, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ।

पहले भी शिकायत, कार्रवाई नहीं; फिर की नई शिकायत

उन्होंने बताया कि 5 मार्च को जिला प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 13 अप्रैल को दोबारा शिकायत की गई है।

अधिकारी बोले- शिकायत आएगी तो जांच कराएंगे

नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक सुरेश सनखेरे ने कहा कि उन्होंने तीन दिन पहले ही पदभार संभाला है और मामला उनके संज्ञान में नहीं है। यदि शिकायत मिलती है तो जांच कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि खराब गुणवत्ता वाले माल के कारण भी उठाव में देरी हो सकती है और रिश्वत मांगने के आरोपों के लिए ठोस प्रमाण जरूरी हैं।

बेटियों की पूजा व नारियों के सम्मान से ही देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

नारी शक्ति पथ संचलन को उप मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झण्डी

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि बेटियों की पूजा व नारियों के सम्मान से ही देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के संबंध में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है। उससे भारत की आधी आवादी को देश हित के निर्णय में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। श्री शुक्ल ने नारी शक्ति पथ संचलन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

कृष्णा राजकपूर आडिटोरियम रीवा में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री जी ने स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने के उपरांत अब संसद में भी प्रतिनिधित्व देने का जो संकल्प लिया है वह अभिनंदनीय है जिसके माध्यम से नारी शक्ति को समुचित सम्मान मिलेगा। श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हित में अनेक योजनाएँ व कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जिसके माध्यम से महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ नारी की पूजा व सम्मान होता है वहां देवता भी वास करते हैं अतः नारी शक्ति का सम्मान करते हुए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ उनके हक के लिये कार्य किये जा रहे हैं। श्री शुक्ल ने कहा कि विन्ध्य की महिलाएँ किसी से पीछे नहीं हैं देश की पहली महिला फाइटर पायलट हमारे यहाँ की हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं के हित में हमेशा ही कार्य किया है। उनका संकल्प है कि हर घर की महिला जागरूक हो, आगे आये और बराबरी के साथ चले। लखपती दीदी, स्वसहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी के साथ ही स्थानीय निकायों में हमें प्रतिनिधित्व मिला और अब नई राह खुल रही है। कार्यक्रम में महिला विदुषी श्रीमती ज्ञानवती अवस्थी ने कहा कि हमारी संस्कृति में मातृ वंदना होती है। मातृ शक्ति को ही सृष्टि की रचना का श्रेय दिया गया है इसलिए वह वंदनीय है। नारी अपने चरित्र से पुरूषों को प्रेरणा देती है इस लिए उसका स्थान सर्वोपरी हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह ने बताया कि नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा में 10 से 25 अप्रैल तक महिलाओं के सम्मान में अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में संभाग स्तर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने मोबाइल फोन से मिस्डकाल कर महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया। अवसर पर मातृ शक्तियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्रीमती पन्नाबाई प्रजापति, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती पूर्णिमा तिवारी, श्रीमती गीता माझी, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र गुप्ता, विधायक मनगवां इंजी. नरेन्द्र कुमार प्रजापति, अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पाण्डेय, सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास शशिश्याम उइके, श्रीमती दर्शना वाकड़े, आशीष द्विवेदी, जीवेन्द्र सिंह सहित बड़ी संख्या में विभागीय अधिकारी, कर्मचारी व मातृ शक्तियाँ उपस्थित रही।

मुख्यमंत्री ने सिवनी मालवा में रोड शो में जनता का किया अभिवादन

नर्मदापुरम-टिमरनी स्टेट हाईवे तरक्की का खोलेगा नया मार्ग : सीएम डॉ. यादव

● प्रधानमंत्री श्री मोदी देशवासियों के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर समान रूप से ध्यान दे रहे हैं ● सिवनी मालवा को मिली 1000 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों की सौगात

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज का दिन भारत के लोकतंत्र के इतिहास का बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी के सबसे बड़े निर्णय नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हुई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहनों के राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। नारी केवल सृष्टि की जननी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की उन्नति की वास्तविक सूत्रधार है। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, तो उसकी नींव में आधी आबादी के सामर्थ्य, संघर्ष और सफलता की कहानियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी सामर्थ्य को संवैधानिक मान्यता देने और लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए नेतृत्व के नए द्वार खोलने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। प्रधानमंत्री श्री मोदी देशवासियों के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी समान रूप से ध्यान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 972 करोड़ से अधिक लागत के 72 किलोमीटर लंबे नर्मदापुरम-टिमरनी स्टेट हाईवे-67 का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य के भूमि-पूजन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को नर्मदापुरम जिले के सिवनी-मालवा में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री और नर्मदापुरम के प्रभारी श्री राकेश सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहर के प्रसिद्ध दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम एवं भगवान बजरंगबली का विधि विधान से पूजन कर हनुमान मंदिर से ही रोड-शो का शुभारंभ किया। रोड-शो के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव क्षेत्र की जनता का अभिवादन किया। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया।

लाड़ली बहनों को अब तक 55 हजार करोड़ रूपए से अधिक राशि दी जा चुकी है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में पहले से ही स्थानीय निकाय और नगरीय निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत पद बहनों के लिए आरक्षित हैं। राज्य सरकार बहनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, राज्य सरकार जो कहती है, उसे पूरा करती है। प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को अब तक 55 हजार करोड़ रूपए से अधिक राशि दी जा चुकी है। लाड़ली बहना योजना की शुरुआत से लेकर अब तक प्रति बहन 40 हजार 500 रुपए से अधिक राशि बहनों के बैंक खातों में आई है। बहनें चिंता न करें, योजना की राशि बढ़कर 1500 रुपए करने के साथ आगे भी जो संभव होगा वह किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। प्रदेश में पहली बार शासकीय स्कूलों के बच्चों को माता यशोदा योजना के अंतर्गत निःशुल्क दूध के पैकेट बांटे जाएंगे। हमारे बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त बनेंगे। प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने और गौपालन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरू की है। इससे हमारे भाई-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने कठिन समय में सड़क पर घायलों की मदद के लिए राहवीर योजना शुरू की है, जिसमें घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25 हजार रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप देने की व्यवस्था है। मुश्किल वक्त में गरीब-जरूरतमंदों की मदद के लिए एयर एम्बुलेंस भी संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन्य जीव और जनजातीय क्षेत्रों को समेटे नर्मदापुरम जिला विविधता से परिपूर्ण है। पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह के नाम पर कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी। नर्मदापुरम में नर्मदा लोक भी बन रहा है। नर्मदापुरम में उद्योग और कृषि के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सड़कें विकास का आधार हैं, इस तथ्य को दृष्टिगत रख नर्मदापुरम जिले में अनेक सड़क परियोजनाओं का कार्य जारी है।

ग्वालियर में एलिवेटेड रोड की 200 फीट लंबी स्लाइड गिरी

1300 करोड़ रुपए की लागत हो रहा है निर्माण

ग्वालियर (नप्र)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बड़ा हादसा हुआ है।1300 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एलिवेटेड रोड की 200 फीट लंबी स्लाइड गिर गई है। स्लाइड खेड़ापति इलाके में गिरी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे में एक मजदूर घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

मौके पर पहुंचे प्रशासन के लोग- वहीं, हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी की स्थिति है। प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई है। हालांकि स्लाइड कैसे गिरी, इसे लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आया है। एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट ग्वालियर शहर के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। शहर को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए इसका निर्माण हो रहा था।

पेयजल और सीवरेज लाइन निर्माण की कठिनाईयां समन्वय से दूर करें : उप मुख्यमंत्री

पेयजल पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने वालों पर लगाएं भारी जुर्माना

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में रीवा नगर निगम के कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा शहर का तेजी से विकास हो रहा है। लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप सड़क, पानी, नाली और पेयजल व्यवस्थाओं में तेजी से विस्तार किया जा रहा है। शहर में निर्माण कार्य समन्वय से करें। पेयजल की पाइपलाइन और सीवरेज लाइन निर्माण की कठिनाईयों को समन्वय से दूर करें। हर घर को पर्याप्त और साफ पानी देना आवश्यक है। निर्माण कार्यों के कारण यदि पेयजल की पाइपललाइन क्षतिग्रस्त होती है तो संबंधित पर भारी जुर्माना लगाएं। शहर में निर्माण कार्य करने वाले विभिन्न विभाग और निर्माण एजेंसियाँ, नगर निगम तथा अन्य एजेंसियों से समन्वय बनाकर निर्माण कार्य करें जिससे पूर्व से निर्मित संरचनाओं को किसी तरह का नुकसान न हो।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत-2 योजना से निर्माणाधीन टंकियों और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शीघ्र लोकार्पण कराएं। इनसे शहर के कई मोहल्लों में मीठे पानी की आपूर्ति हो सकेगी।

सीवरेज लाइन के शेष बचे लगभग सौ किलोमीटर निर्माण कार्य को तय समय से पूरा कराएं। नगर निगम के अधिकारी इसकी सतत निगरानी करें। जयंती कुंज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से 13900 घरों के सीवरेज का ट्रीटमेंट होगा। इसके सुधार का कार्य शीघ्र शुरू कराएं। जयंती कुंज सहित बाबा घाट, बिछिया और विवेकानंद वार्ड में निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का शीघ्र लोकार्पण कराएं। शहर को साफ-सुथरा रखने और पर्यावरण की समुचित सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है। सीवरेज लाइन के निर्माण के लिए खुदाई का कार्य जहाँ तक संभव हो मैन्युअल कराने का प्रयास करें। मशीनों से खुदाई करने पर ही पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएनजी गैस के प्रतिनिधि प्रत्येक मोहल्ले में शिविर लगाकर लोगों को पाइप्ड नेचुरल गैस का कनेक्शन दें। इससे परिवारों को सिलेण्डर से मुक्ति मिलेगी। शासन द्वारा निर्धारित 2800 घरों को कनेक्शन देने का लक्ष्य दो माह में पूरा करें। बैठक में निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि ने बताया कि रीवा में 363 किलोमीटर सीवर लाइन का निर्माण किया जाना है। इनमें से 252 किलोमीटर लाइन का निर्माण पूरा हो गया है। ढेकहा, रतहरा रोड, पीटीएस और बाजार में निर्माण कार्य शेष है। इस साल के अंत तक शेष कार्य पूरा हो जाएगा। शहर में तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूरा हो गया है। शेष तीन का कार्य दो माह में पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि नगर के निर्माण कार्यो तथा पेयजल व्यवस्था की हर सप्ताह टीएल बैठक में समीक्षा की जाएगी।

थार-बलेनो की टक्कर

मां-बेटे की मौत, बेटी समेत 3 घायल

खंडवा में शादी की खरीददारी करने जा रहे थे, 21 अप्रैल को थी शादी

खंडवा (नप्र)। खंडवा जिले के मूंदी थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर थार और बलेनो कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। भिड़ंत में मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, ग्राम जलवा निवासी सौरभ राठौर (28) अपनी मां सुमन बाई (58), बहन सारिका, रिश्तेदारों के साथ कार से मूंदी की ओर आ रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही थार वाहन ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि सौरभ और उनकी मां सुमन बाई की मौके पर ही मौत हो गई।

शादी की खरीदारी के लिए जा रहा था परिवार

परिवार में कुछ ही दिनों में शादी का कार्यक्रम था, 21 अप्रैल को सारिका की शादी होने के चलते मूंदी में खरीददारी के आ रहे थे। जिससे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन इस हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों के पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस हादसे में सारिका राठौर, रविंद्र राठौर (दोनों पिता राजेंद्र, निवासी जलवा) और रविंद्र (पिता दिनेश, निवासी देशगांव) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को पहले मूंदी में प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल खंडवा भेजा गया।

मप्र में बजट ज्यादा कर्ज

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय सेहत को लेकर खतरे की घंटी बज चुकी है। मंगलवार को राज्य सरकार ने 1800 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया है। इस बार कर्ज लेने की प्रक्रिया पिछले साल के मुकाबले एक महीने पहले ही शुरू कर दी गई है। इसके पीछे की मुख्य वजह केंद्र से मिलने वाले टैक्स के हिस्से में हुई कटौती और आरबीआई के नए नियम हैं, जिसने सरकार को शुरुआती महीनों में ही बाजार से पैसा उठाने पर मजबूर कर दिया है।

बजट से ज्यादा हुआ कर्ज- मध्य प्रदेश का चालू वित्त वर्ष (2026-27) का बजट करीब रू. 4,38,317 करोड़ का है, लेकिन राज्य पर कुल सार्वजनिक कर्ज अब रू. 5,20,000 करोड़ के पार निकल गया है। यानी सरकार की कुल कमाई और खर्च के बजट से भी करीब 80,000 करोड़ रुपये ज्यादा का कर्ज प्रदेश पर लदा हुआ है।

गृह मंत्रालय भारत सरकार

हमारी जनगणना हमारा विकास

(जनगणना 2027 का पहला चरण)
स्व-गणना (Self Enumeration) से जुड़े सामान्य प्रश्न और उत्तर (भाग-1)

स्व-गणना क्या है?
स्व-गणना एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें आप प्रगणक की प्रतीक्षा किए बिना, स्वयं SE पोर्टल (se.census.gov.in) पर अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं

- क्या स्व-गणना अनिवार्य है?
  नहीं, यह अतिरिक्त सुविधा है, यदि आप स्व-गणना नहीं करते तो प्रगणक आपके घर आकर जानकारी दर्ज करेगा
- क्या मैं किसी भी भाषा में स्व-गणना कर सकता / सकती हूँ?
  यह सुविधा हिंदी, अंग्रेजी और 14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है
- क्या स्व-गणना के लिए इंटरनेट जरूरी है?
  हाँ, पोर्टल तक पहुँचने और जानकारी भरने के लिए इंटरनेट आवश्यक है
- क्या मेरी जानकारी सुरक्षित है?
  हाँ, सभी डेटा सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड और सरकारी सर्वरों में संरक्षित है
- SE ID क्या है और इसका उपयोग क्या है?
  सबमिशन के बाद आपको एक विशिष्ट 11 अंकों की SE ID मिलेगी (SMS / email से), जिसे प्रगणक के आने पर उन्हें दिखाना आवश्यक होगा
- यदि SE ID भूल जाएँ तो क्या करें?
  पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से SE ID पुनः प्राप्त की जा सकती है
- क्या स्व-गणना के बाद भी प्रगणक आएगा?
  हाँ, प्रगणक आपके घर आएगा और SE ID के आधार पर जानकारी की पुष्टि करेगा
- क्या मुझे कोई दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता है?
  नहीं, किसी भी दस्तावेज़ को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है
- क्या पोर्टल पर सहायता उपलब्ध है?
  हाँ, पोर्टल पर, यूज़र गाइड, फ्लोचार्ट, ट्यूटोरियल वीडियो, FAQs और टूलटिप्स के रूप में सहायता उपलब्ध है

टोल फ्री - 1855

CBC 19108/13/0023/2627

चलो निभाएं अपनी ज़िम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी
CensusIndia2027